CNEWS सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-137
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार

फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना क्योंकि...
इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी!

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर, गुरुवार 22 अगस्त 2024

बदनीयती के 'महिषासुर': कोलकाता, बदलापुर के बाद अब छत्तीसगढ़ में दरिंदगी, महिला से 8 लोगों ने किया गैंगरेप, इस बीच एडीआर ने उजागर किया जन प्रतिनिधियों का भी चरित्र

जब 'माननीयों' का दामन ही मैला तो अब बचा ही क्या?

नई दिल्ली। कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र के बदलापुर तक लोगों में गुस्सा है। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित हो गया। बंगाल की बेटियों की सुरक्षा की चिंता में सब जुटे ही थे कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में 4 साल की दो बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत हो गई। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि रायगढ़ जिले में 27 वर्षीय एक आदिवासी महिला के साथ आठ लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार को पुसौर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई जब पीड़िता रक्षाबंधन त्योहार मनाने के बाद एक स्थानीय मेले में घूमने जा रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने मंगलवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार, कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसे रोक लिया और उठाकर जबरन पास के एक तालाब के किनारे ले गए। वहां ले जाकर सभी ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में आगे की जांच जारी है। बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला ने बताया कि महिला सोमवार को एक स्थानीय मेले में गई थी। वह आरोपियों में से एक को जानती थी और उन दोनों ने स्थानीय बाजार के पास मिलने का फैसला किया। जब मुख्य आरोपी उससे मिला तो वह अन्य आरोपी लोगों के साथ था। महिला के अनुसार, उसके साथ आठ लोगों ने बलात्कार किया, जो मुख्य आरोपी के साथ थे। घटना के बाद आरोपियों ने महिला को धमकी भी दी थी। उसके बाद वे लोग वहां से भाग गए। आईजी ने बताया कि मंगलवार रात तक हमने छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। दो आरोपी फरार हैं। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (न्यूज) द्वारा बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर ही महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं।

बीजेपी के नेता पहले नंबर पर, दूसरे पर कांग्रेसी

रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक दलों में सबसे अधिक भाजपा के 54 सांसद और विधायक हैं, जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले हैं। इसके बाद कांग्रेस के 23 और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के 17 सांसद-विधायक हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही पांच-पांच मौजूदा सांसद-विधायक बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

टिकट देने से परहेज करने की जरूरत

चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर उन लोगों को जिन पर बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों के आरोप हैं। रिपोर्ट में सांसदों-विधायकों के खिलाफ अदालती मामलों की त्वरित सुनवाई तथा पुलिस द्वारा पेशेवर तरीके से और गहन जांच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है।

महिला उत्पीड़न मामलों में आरोपी हैं 151 सांसद-विधायक

देश में 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (न्यूज) द्वारा बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे अधिक है, जो महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामलों में आरोपी हैं। एडीआर ने 2019 और 2024 के बीच चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,809 हलफनामों में से 4,693 की जांच की। जिसके बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे 16 सांसदों और 135 विधायकों को चिह्नित किया गया।

प. बंगाल में सबसे ज्यादा 'चरित्र में दागदार' नेता

एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे 25 सांसदों और विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, जिसके बाद आंध्रप्रदेश में 21 और ओडिशा में 17 सांसद-विधायक हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या तथा ठाणे में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

16 मौजूदा सांसद और विधायकों पर धारा 376

रिपोर्ट के अनुसार, 16 मौजूदा सांसद और विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार से संबंधित मामलों की जानकारी दी है, जिसके लिए न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इनमें से दो सांसद और 14 विधायक हैं। आरोपों में एक ही पीड़िता के खिलाफ बार-बार अपराध की घटनाएं भी शामिल हैं, जो इन मामलों की गंभीरता को और अधिक रेखांकित करता है।

मप्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब 'चेहरे' की जरूरत नहीं

भोपाल। मध्यप्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित अधिकांश सेवाएं अब फेसलेस प्रक्रिया के तहत हैं। अब इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य में प्रदूषण परीक्षण केंद्र (पीटीसी) संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन पोर्टल पर एकीकृत कर ऑनलाइन जारी किये जाते हैं। यह प्रणाली प्रारंभ में भोपाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरी की गई थी। परिवहन विभाग अब इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कर रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले 6 महीनों में, मानवीय हस्तक्षेप के बिना पारदर्शी तरीके से वाहनों पर फिटनेस परीक्षण करने के लिए राज्य के ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में चल रही ड्राइविंग लाइसेंस की लेट लतीफी पर आरटीओ जितेंद्र शर्मा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, तो लोगों को मोबाइल पर भेजे गए डिजिटल लाइसेंस को ही वैध मानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्ड की डिलीवरी में मामूली देरी हो सकती है, लेकिन यह लाइसेंस की वैधता को प्रभावित नहीं करता। शर्मा ने कहा, ह्यजब आपके मोबाइल पर लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, तो आपका लाइसेंस बन जाता है।

छतरपुर में भीड़ का थाने पर हमला, जमकर किया पथराव

छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर में मोहम्मद पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। एफआईआर दर्ज कराने आए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने थाने पर ही पथराव कर दिया। कोतवाली थाने पर पथराव किया। भीड़ द्वारा किए गए इस पथराव में थाना इंचार्ज सहित तीन सिपाही घायल हो गए। भीड़ ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मुंबई में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पर किसी युवक के द्वारा की गई टिपणी को लेकर एफआईआर कराने मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग थाने पहुंचे थे। ये लोग वहां प्रदर्शन करने लगे। शुरू में 4 से 5 सौ लोग थे। पुलिस ने सभी को बाहर कर दिया।

सीबीआई के रडार पर आए ईडी अधिकारी ने कर ली आत्महत्या

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में आने वाले ईडी के एक अधिकारी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। संभावना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। ईडी अधिकारी आलोक कुमार पंकज का शव दिल्ली के पास साहिबाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिला। गाजियाबाद के रहने वाले आलोक कुमार नई दिल्ली में ईडी में प्रतिनियुक्ति पर थे। इससे पहले उन्होंने आयकर विभाग में काम किया था। हाल ही में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने उनसे दो बार पूछताछ की थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया था। आलोक कुमार पंकज का नाम रिश्वत मामले में तब सामने आया था जब ईडी के एक सहायक निदेशक संदीप सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

सीबीआई को एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी कि संदीप सिंह ने उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये की मांग की थी। इसके बाद एजेंसी ने जाल बिछाया और सिंह को दिल्ली में 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। संदीप सिंह ने कथित तौर पर मुंबई के एक जौहरी से भी रिश्वत ली थी, जिसके स्टोर पर पहले ईडी ने छापा मारा था। इसी मामले में एफआईआर में संदीप सिंह के साथ आलोक कुमार पंकज को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले के बाद संदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने ईडी अधिकारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है। साथ ही कथित आत्महत्या के कारण का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी है।

बिहार-झारखंड और राजस्थान में भारत बंद का ज्यादा असर

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। देशभर के 21 संगठनों की तरफ से यह बंद आहूत किया गया था। संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को क्षति होगी। भारत बंद का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला। बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। भारत बंद का असर बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे कई राज्यों में देखने को मिला। कई संगठन इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बंद का बिहार और झारखंड में पूरा असर देखने को मिला।

दुमका में भीम आर्मी, छात्र समन्वय समिति और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकर्ताओं ने सड़क और दुकानों को बंद करवा दिया। शहर की फूलों झानो चौक पर ट्रकों को जाम कर दिया गया। नालंदा में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ अभियान के तहत द ग्रेट भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक और देवीसराय मोड़ पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने देवीसराय चौक पर जाम लगाकर आगजनी की और जेसीबी मशीन पर चढ़कर हंगामा किया। जहानाबाद-बिहार शरीफ-पटना-रांची रोड और नवादा-बिहार शरीफ मुख्य सड़क मार्ग को भी जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित करने के साथ पटना, हाजीपुर, दरभंगा, जहानाबाद और बेगूसराय जिलों में कई स्थानों पर कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित रोड ट्रैफिक को अवरुद्ध करने की कोशिश की। इस पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

मप्र में भर्ती पर भर्ती निकाल रहा स्वास्थ्य विभाग....नहीं मिल रहे डॉक्टर

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग में हजारों की तादाद में भर्तियां कर रही है। बावजूद इसके प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। जिनका चयन हो भी रहा तो वे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा ली गई विभागीय अधिकारियों की बैठक में सामने आई। पिछले साल प्रदेश में 15 अलग-अलग पदों के लिए सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई है, जिसमें से 1607 उम्मीदवार ही चयन प्रक्रिया में खरे साबित हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में ज्वॉइन करने का काम शुरू कराया गया तो 360 चयनित उम्मीदवारों ने जॉइन ही नहीं किया। इसके बाद 230 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट के जरिए जॉइन कराया है। इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर 3353 चिकित्सक पदों को भरने का काम शुरू किया है।

डेप्युटी सीएम ने की समीक्षा उप मुख्यमंत्री और मंत्री लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राजेंद्र शुक्ल रिक्त पदों को जल्द से भरने के लिए बैठकें ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और अफसरों से जल्दी रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है। शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मैनपावर उपलब्धता के संबंध में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की।

सीधी भर्ती के लिए जारी हो चुके हैं विज्ञापन उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सक, विशेषज्ञ, सहायक चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती के लिए आवश्यक कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रथम श्रेणी के 1085 पदों के लिए लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। वहीं, द्वितीय श्रेणी के पदों में 895 चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। द्वितीय श्रेणी के 1373 पदों में भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

CNEWS सिटी चीफ
सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार
Fastest Growing Media Network

अवश्यकता है

इंदौर भोपाल जिले के सभी तहसीलो में दैनिक अख़बार और डिजिटल रिपोर्टर की।
डिजिटल और प्रिंट के लिये मार्केटिंग टीम (मेल/फीमेल) एवं हेल्परो की अवश्यकता हैं
डिजिटल मीडिया का क्रान्तिकारी कदम
डिजिटल भारत में खबरों के लिए देखे सिटी चीफ न्यूज़
रिपोर्टर बनने के लिए सम्पर्क करे
9755996590

सिंगल कॉलम

उम्रकैद की सजाए पाए कैदी ने सेंट्रल जेल में की जान देने की कोशिश

इंदौर। इंदौर सेंट्रल जेल में एक कैदी ने बुधवार को सुसाइड का प्रयास किया। कैदी ने गले में कील घुसा ली। उसे उपचार के लिए गले में फंसी हुई कील के साथ एमवाय लेकर आया गया है। कुछ दिन पहले इसी कैदी ने जेल में लोहे की बाल्टी का कुंदा फंसा लिया था। लेकिन तब भी बच गया था। सेन्ट्रल जेल के कैदी दीपक पुत्र जगदीश निवासी इंदौर को जेल स्टाफ घायल अवस्था में बुधवार दोपहर एमवाय लेकर पहुंचा। दीपक के गले में कील घुसी हुई थी। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों से पूछा तो बताया कि दीपक ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया। दीपक ने कुछ माह पहले जिला जेल में बाल्टी के कुंदे को गले में फंसाकर सुसाइड का प्रयास किया था। लेकिन तब भी उसकी जान बच गई थी। दीपक पहले विचाराधीन कैदी था। पॉस्को एक्ट की धाराओं में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके बाद उसे जिला जेल से सेन्ट्रल जेल भेजा गया। दीपक अब तक तीन बार सुसाइड का प्रयास कर चुका है।

अलग-अलग पेड़ों पर फंदे से लटकते मिले दो शव, एक की हुई शिनाख्त

इंदौर। इंदौर के बाणगंगा और तेजाजी नगर इलाके में दो लोगों ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।बाणगंगा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह एमआर 4 स्थित लक्ष्मीबाई नगर में एक पेड़ पर शव टंगे होने की सूचन मिली। मौके पर पहुंचने पर उसकी शिनाख्त भागचंद निवासी भगतसिंह नगर के रूप में हुई है। वह अलसुबह अपने घर से निकल गया था। पुलिस हत्या के बिंदू पर भी जांच कर रही है। वहीं रालामंडल में भी मंगलवार शाम करीब 6 बजे 35 साल के युवक का शव बबूल के पेड़ पर लटका मिला। युवक की शिनाख्त नही हो पाई है। आसपास के गांव और इलाके में पुलिस ने पहचान के फोटो भेजे है।

रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की बाथरूम में फिसलने से मौत

इंदौर। इंदौर के लसूड़िया इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की बाथरूम में फिसलने से मौत हो गई। घायल होने के बाद उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उन्हें एमवाय रेफर किया गया। जहां मंगलवार शाम उनकी मौत हो गई। लसूड़िया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दिलीप(36) पुत्र टिंकुश त्रिकरा निवासी स्कीम नंबर 78 अपने घर की बाथरुम में शनिवार रात करीब 2 बजे गिर गए थे। अलसुबह पत्नी रेखा ने देखा तो वह बाथरूम में पड़े थे। पत्नी रेखा ने घटना की सूचना परिवार के सदस्यों को दी। दिलीप को उपचार के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां मंगलवार सुबह उन्हें होश नहीं होने के चलते एमवाय शिफ्ट किया गया। परिवार ने बताया कि दिलीप का वेल्डिंग का शॉप था। परिवार में दो बेटी और पत्नी है। परिवार ने बताया कि दिलीप के पिता टिंकुश पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं।

इंदौर में एक साथ तैयार हो रहे दस ब्रिज, तीन बड़े मार्गों की राह आसान

इंदौर। दस साल पहले इंदौर शहर के लिए एक ब्रिज मंजूर होने में एक दो साल लग जाते थे और उसके निर्माण में तीन से चार साल का समय लग जाता था। राजकुमार और केसरबाग ब्रिज सात साल में बनकर पूरे हुए, लेकिन अब शहर में एक साथ दस ब्रिजों का काम चल रहा है। आने वाले दिनों बायपास, बीआरटीएस, इंदौर-उज्जैन मार्ग और रिंग रोड की राह आसान हो जाएगी। फ्लायओवर और रेलवे ब्रिज ट्रैफिक की राह आसान बनाते है। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड के चौराहों पर पहले काफी ट्रैफिक रहता था, लेकिन अब खजराना से आईटी चौराहे तक 25 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। खजराना ब्रिज और मूसाखेड़ी ब्रिज बनने के बाद समय और कम लगेगा। बांबे अस्पताल और रेडिसन चौराहे के अलावा आईटी चौराहे तक रिंग रोड के सभी जंक्शनों पर ब्रिज बन चुके हैं। बीआरटीएस पर निरंजनपुर चौराहा पर लोक निर्माण विभाग ब्रिज बना रहा है। इसके अलावा भंवरकुआ चौराहा पर इंदौर विकास प्राधिकरण ब्रिज तैयार कर रहा है। छह किलोमीटर हिस्से में एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना तैयार की गई, लेकिन इस कॉरिडोर का मामला अधर में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस ब्रिज का भूमिपूजन छह माह पहले किया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। राजेंद्र नगर क्षेत्र के रेलवे क्रासिंग पर ब्रिज का काम शुरू है। इसके अलावा फुटीकोठी चौराह पर 70 प्रतिशत ब्रिज बन चुका है।लवकुश चौराहा पर डबल डेकर ब्रिज बन रहा है। बायपास पर एमआर-10 जंक्शन के अलावा रालामंडल और राऊ सर्कल पर ब्रिज बन रहे है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि आने वाले वर्षों में शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी ब्रिज बनाए जाएंगे।

भीड़ भरे बाजारों के लिए व्यवस्थाः इंदौर कलेक्टर का फैसला- दुकानदार नगर निगम के पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करेंगे अपने वाहन, शुल्क चुकाना होगा

दुकान के सामने केवल ग्राहक के वाहन ही खड़े होंगे

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के भीड़भाड़ वाले सराफा, राजवाड़ा, जेल रोड़ तथा इसके आसपास के बाजारों के दुकानदार अपने वाहन नगर निगम के मल्टीलेवल तथा अन्य पार्किंग स्थलों पर पार्क करेंगे। इसके लिए उनसे नगर निगम द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। चंद समय के लिए ग्राहक के वाहन दुकानदार अपनी दुकान पर खड़े कर सकेगा। यह निर्णय कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर के मध्य क्षेत्र के मार्केट एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बुधवार को हुई बैठक में लिए। बैठक में उन्होंने शहर के मध्य क्षेत्र के बाजारों के दुकानदारों तथा ग्राहकों आदि के वाहन सुव्यवस्थित रूप से पार्क करने के संबंध में विचार-विमर्श किया।

प्रशासन ने कहा है कि यातायात तथा पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चौराहों को सुधारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अभियान चलाकर सड़क और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने का कार्य भी चल रहा है। इसी तरह बेसमेंट में पार्किंग स्थल का अन्य उपयोग करने वालों को भी नोटिस जारी कर एक माह का समय दिया गया है। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा तथा अपर आयुक्त एन.एन. पाण्डे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि हम सकारात्मकता से शहर के हित में काम करेंगे और इसके लिए हर माह के दूसरे बुधवार बैठक करेंगे।

सड़कों और फुटपाथों के अतिक्रमण पहले हटाए जाएं

इस बैठक में व्यापारिक संगठनों ने कहा कि व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग निर्धारित स्थानों पर हो और यातायात सुगम हो, इसके लिए तय नीति का हम पालन करेंगे लेकिन, उससे पहले सड़क और फुटपाथ का अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। इस पर जेलरोड एसोसिएशन के राजकुमार शर्मा ने कहा कि अत्यधिक शुल्क वहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हम शासन प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि मूल्य निर्धारण पर विचार-विमर्श करें। इंदौर रिटेल गारमेन्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि हम विगत 3 वर्षों से सड़क के कब्जाधारियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, निगम रिमूवल कार्रवाई के चार दिन बाद फिर वही स्थिति खड़ी होती है। इस व्यवस्था का जब तक स्थायी निदान नहीं होता है तब तक यातायात प्रबंधन का मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। पहली पहल सड़क के कब्जे हटाकर ही हो। इस दिशा में कलेक्टर आशीष सिंह ने उपस्थित निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और संबंधित अधिकारी को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि हम फुटपाथ को लेकर मुहिम को सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। स्पॉट फाइन भी लागू करेंगे। इस अहम बैठक के सुझाव के अमलीकरण परिणाम का सूचकांक होगा। हम हर माह के दूसरे बुधवार व्यापारिक संगठनों के साथ चर्चा करेंगे।

300 और 1400 रुपए पार्किंग शुल्क लगेगा हर माह

बैठक में पार्किंग शुल्क हर माह 300 रुपए दोपहिया प्रति वाहन और चार पहिया वाहन का 1400 रुपए लेना तय किया। अक्षय जैन ने बताया कि इतना शुल्क पहले से ही लिया जा रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि तय हुआ कि एक सप्ताह में शहर के मध्य व्यावसायिक संस्थानों के वाहन अब सड़क के बजाय क्षेत्र के निर्धारित पार्किंग में मासिक पास (सशुल्क) खड़े किए जाएंगे। जेलरोड, कोठारी मार्केट, एमजी रोड के आसपास के व्यापारिक संस्थानों के वाहन महाराजा कॉम्प्लेक्स, जिला न्यायालय के पीछे पोद्दार कॉम्प्लेक्स वाली जगह पर होंगे। मेहतानी मार्केट रोड वाले पालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स पार्किंग में वाहन पार्क कर सकेंगे। इंदौर रिटेल गारमेन्ट्स एसोसिएशन के लिए सुभाष चौक पार्किंग को अधिकृत किया है।

एसोसिएशन देगा दुकानदारों की अधिकृत सूची

पदाधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था को लागू होने के पूर्व निगम के अधिकारी और एसोसिएशन के पदाधिकारी यातायात प्रभारी की टीम के साथ वाहन पार्किंग व्यवस्था का पूरा रोड मैप बनाएंगे। इसके साथ ही गूगल मैप पर उसका आकार चिन्हित होगा। दुकानदार और उनके स्टाफ की वाहन पार्किंग को लेकर एसोसिएशन ही अधिकृत कर निगम को सूची देगी।

बैठक में सराफा एसोसिएशन के अनिल रांका ने कहा कि व्यापारिक संगठन साथ देने को तैयार हैं, मगर तय व्यवस्थाओं को जमीनी हकीकत देने के लिए नीचे का अमला ईमानदारी से काम करे। कलेक्टर आशीष सिंह ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि जो तय होगा उसके परिणाम पर भी सब मिलकर आकलन करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव बने संजय दुबे

11 दिन में तीसरी बार आईएएस अधिकारियों के तबादले, 12 अफसर इधर से उधर

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल/इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने 11 दिन में तीसरी बार आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इससे पहले मंगलवार को भी अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बुधवार को एक बार फिर से सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईएएस अधिकारी संजय दुबे को सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को प्रमुख सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधवार को जारी लिस्ट में किसी भी जिले के कलेक्टर को नहीं बदला गया है। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक इलैया राजा टी को अपर सचिव, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि मंगलवार को भी राज्य सरकार ने कई अधिकारियों के तबादले किए थे। श्रीमन शुक्ला को शहडोल संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मनीष रस्तोगी को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग बनाया गया है। रजिस्टार, उपभोक्ता प्रतितोषण विवाद आयोग मनीष सिंह को

आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना, भोपाल बनाया गया है। उप सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग राखी सहाय को प्रबंध संचालक, वित्त निगम, इंदौर बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर आशीष तिवारी को उप सचिव, जल संसाधन विभाग बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर जयति सिंह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन बनाया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम कीर्ति खुरासिया को उपसचिव मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी राहुल नामदेव धोटे को उप सचिव, नर्मदा विकास घाटी बनाया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा योगेश तुकाराम भरकट को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रीवा, सौरभ संजय सोनवणे को आयुक्त, नगर पालिक निगम बनाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नीमच गुरु प्रसाद प्रबंध संचालक, स्वान बनाया गया है।

सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जल्द शुरू होगी इवनिंग ओपीडी

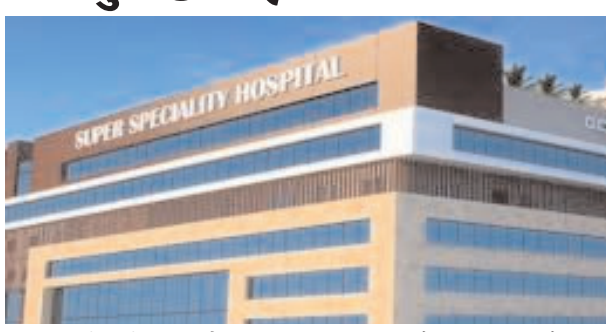

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब जल्द ही इवनिंग ओपीडी शुरू होगी। लम्बे समय से यह सुविधा शुरू होने के प्रयास चल रहे थे। हाल ही में हुई एमजीएम मेडिकल कॉलेज की कार्यकारी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने वाली है। इसके बाद रोज शाम 4 से 6 बजे तक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट बैठेंगे। मरीज को डॉक्टर को दिखाने का चार्ज 600 रुपए प्रस्तावित है। इसमें दवाई और जांच मुफ्त होंगी।इस राशि से डॉक्टर, नर्स और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान होगा। शाम की ओपीडी में हॉस्पिटल के ही विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे जो अपनी सेवाएं देंगे। इस व्यवस्था में मरीजों को दवाओं और जांच के लिए भुगतान करना होगा। इसके पूर्व एमवायएच अस्पताल में भी शाम की ओपीडी के लिए इसी तरह के प्रस्ताव पर पहले भी विचार किया गया था। तब डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की रुचि नहीं होने के कारण यह प्रयोग सफल नहीं हो सका था। दरअसल कई डॉक्टर पहले से ही अपनी निजी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। अब इस प्रस्ताव के सफल होने की इसलिए संभावना है क्योंकि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में शाम के समय विशेषज्ञों को दिखाने के लिए मरीजों के पास निजी क्लिनिक या अस्पताल ही विकल्प रहता है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर की फीस और जांच के लिए मोटी रकम चुकाना पड़ती है लेकिन अब यहां इन्हें सिर्फ डॉक्टर की फीस ही देना होगी। मरीजों से मिलने वाले शुल्क से 300 रुपये डॉक्टर को मिलेंगे। 100 रुपये नर्सिंग स्टाफ को और 50 रुपये तृतीय श्रेणी कर्मचारी को दिए जाएंगे। वहीं 150 रुपये प्रशासनिक राजस्व में जमा होंगे। डीन डॉ. संजय दीक्षित ने बताया कि अभी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्दी मंजूरी मिलने के संकेत हैं। अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग जल्द ही 20 लाख रुपए मूल्य की एक वीडियो ईईजी मशीन खरीदी जा रही है। इसकी मंजूरी भी एमजीएम कॉलेज ने दे दी है। ऐसे ही डायलिसिस यूनिट में आउट सोर्सिंग के माध्यम से तीन डायलिसिस टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाएगी। उधर, कोलकाता रेप-मर्डर केस के बाद एमवाय अस्पताल सहित एमजीएम से संबद्ध सभी अस्पतालों में महिला डॉक्टरों के लिए अलग से ड्यूटी रूम पर अमल किया जा रहा है। एमवाय अस्पताल में तो इसकी शुरूआत भी हो गई है। दरअसल पहले मेल-फीमेल के लिए हर फ्लोर पर दो-दो ड्यूटी रूम की व्यवस्था थी। अब नई व्यवस्था में उनके ड्यूटी रूम में बेड, रेफ्रिजरेटर, आरओ वाटर सहित हाइजीन मेंटेन किया जाएगा।

बेटी से बात करने पर शादीशुदा युवक को चाकू मारे

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के एरोड्रम इलाके में शादीशुदा युवक वहीं रहने वाली एक युवती से मोबाइल पर बात करता था। शादीशुदा होने के चलते युवती के परिवार को यह बात ठीक नहीं लगी। इसके चलते उन्होंने युवक को एरोड्रम इलाके में घेरकर चाकू मारे। सड़क पर मरा हुआ छोड़कर भाग गए। बाद में युवक को गंभीर हालत में एमवाय भेजा गया। यहां उसका एमवाय में उपचार चल रहा है।

एरोड्रम पुलिस ने हेमा राणा की शिकायत पर कमल सिंह चौहान, उसके बेटे युवराज और राज पर 109 3(5) की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अजय पुत्र सुमेर सिंह राणा, निवासी गांधी पैलेस चंदन नगर पर एरोड्रम इलाके के 60 फीट रोड पर मंगलवार को चाकू से हमला कर दिया। हेमा राणा ने बताया कि अजय उसका पति है। जिसे गाल, पेट, सिर और अन्य जगह चाकू लगे हैं। पुलिस के मुताबिक अजय राणा आरोपी की बेटी से मोबाइल पर बात करता था। पूर्व में इस बात को लेकर विवाद भी हुआ था। परिवार ने इस बात को लेकर हिदायत दी थी।

लेकिन अजय नहीं माना। इसके बाद आरोपियों ने उसे घेरकर हमला कर दिया। उसका आईसीयू में उपचार चल रहा है।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के बाद लिया गया एक्शन

मध्यप्रदेश में 9 इंजेक्शन और दवा के बड़े लॉट पर बैन

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट के आधार पर, मध्य प्रदेश में 9 दवाओं के बड़े लॉट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये दवाएं अब राज्य के किसी भी अस्पताल में उपयोग नहीं की जा सकतीं। प्रतिबंधित की गई सभी दवाएं इंजेक्शन के रूप में थीं और इनमें कुछ जीवन रक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक्स और मल्टी विटामिन शामिल थे। मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीपीएचएससीएल) ने सभी जिलों के डीन, सीएमएचओ, सुपरिनटेंडेंट सहित पत्र जारी कर प्रतिबंध लगा दिया है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि कुल 12 दवाओं की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई थी, जिनमें से 9 को शुरूआत में

प्रतिबंधित कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि इन लॉट का तब तक उपयोग नहीं किया जाए जब तक कि आदेश जारी न हो।

लैब जांच में दो ड्रग्स की क्वालिटी घटिया मिली

एमजीएम कॉलेज की रिपोर्ट मिलने के बाद, सैंपल को जांच के लिए सेंट्रल ड्रग्स लैब कोलकाता भेजा गया था। वहां से दो की जांच रिपोर्ट मिल गई है, जबकि सात की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। लैब की जांच में 2 की रिपोर्ट नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी (एनएसक्यू) की मिली है। एनड्राइड इंजेक्शन वड़ोदरा-गुजरात और एंड्रेनेलिन इंजेक्शन हिमाचल प्रदेश की कंपनी का है। रिपोर्ट के अनुसार, टेस्टिंग में यह दवा आईपी के अनुरूप नहीं मिली यानी क्वालिटी खराब है। इन इंजेक्शन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने और स्थिर रखने के लिए किया जाता था। इंजेक्शन में हेपरिन, एट्रोपिन, डोपामाइन, नाइट्रोग्लिसरिन, फेंटेनल आदि दवाएं शामिल थीं जो जीवन रक्षक दवाएं भी हैं।

तीन अन्य दवाओं की जांच अधूरी जानकारी के कारण अटक गई है। औषधि प्रशासन ने संबंधित कंपनियों को पत्र भेजकर टेस्टिंग के लिए रैफरेंस स्टैंडर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इनमें एट्रोपिन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, हेपरिन कैल्शियम ग्लूकोनेट और नाइट्रोग्लिसरिन आदि की टेस्टिंग की जानी है।

दवाओं की जांच कराना नियमित प्रक्रिय डीन डॉ. संजय दीक्षित ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 12 दवाओं की जांच रिपोर्ट में कुछ समस्याएं थीं। इनमें से एक की रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है। तीन-चार दिन पहले एमपीपीएचएससीएल ने इनमें से 9 दवाओं के बारे में निर्देश जारी किए हैं। दवाओं की जांच कराना एक नियमित प्रक्रिया है।

नितिन गडकरी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की एक घंटे तक बात

गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में होंगे 1040 करोड़ रुपए के काम

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर-चंबल के विकास के लिए लगातार एक्टिव हैं। पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान विकास के रोडमैप पर बैठक की थी। बैठक के दौरान सामने कई परियोजनाओं को लेकर सवाल आए थे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिले अशोकनगर, गुना और शिवपुरी के सड़क, पुल और अन्य निमार्णों की मांग की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष को भी साथ लेकर आए थे।

इस बैठक में पहले से निर्धारित प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के साथ-साथ विधायकों और जिला अध्यक्ष की भी नई मांगों को सुना।

सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स पर तुरंत मौखिक स्वीकृति भी दे दी।

एक घंटे तक चली मीटिंग

वहीं, नितिन गडकरी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये बैठक एक घंटे से अधिक चली । दोनों के बीच मराठा कनेक्शन भी देखने को मिला , मराठी में दोनों ने खूब बात की , हंसी मजाक के साथ प्रोजेक्ट की चर्चा हुई । इस बैठक में भोपाल से कई एनएचएआई के कई अधिकारी भी जुड़े थे और कई अधिकारी मीटिंग में भी साथ भी मौजूद थे ।

1040 करोड़ रुपए के अधिक के प्रोजेक्ट

वहीं, मीटिंग के दौरान अचानक छड़ी लेकर खुद नितिन गडकरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रोजेक्ट समझाने लगे। इस दौरान नितिन गडकरी सारी बातों को गौर से सुनते रहे।

गुना जिले के लिए प्रोजेक्ट

1. गुना जिले के रिंग रोड निर्माण कार्य प्रोजेक्ट (19 किलोमीटर, लागत-145 करोड़)
2. अनारद से निहाल देवी मार्ग (चौड़ीकरण) (41.76 किलोमीटर, लागत- 50 करोड़)

अशोकनगर के लिए सौगात

1. अशोक नगर रिंग रोड (37 किलोमीटर, लागत- 276 करोड़)
2. चंदेरी - नई सराय से बदरवास वहाया अखाई घाट मार्ग (22.5 किलोमीटर, लागत- 57 करोड़)
3. मूंगावली -अशोक नगर विदिशा मार्ग (47.6 किलोमीटर, लागत- 97 करोड़)

शिवपुरी जिले के लिए यह हैं प्रोजेक्ट

1. कोलारस की माडा गणेशखेड़ा रन्नौद रोड से नेनागिर तक वाया सिंघारई अमहरा इंदार खातौरा बिजरोनी बदरवास बरई अगरा धुंआ - नैनागिर तक सिंगल रोड को दो लेन (7) चौड़ी रोड बनाना (सरक्यूलर मार्ग) (70 किलोमीटर, लागत -140 करोड़)
2. फॉर लेन रिंग रोड़ निर्माण कार्य (14 किलोमीटर, लागत- 65 करोड़)
3. भितरगवां से नयागांव व्हाया कमालपुर मंगुली-पड़रा- मुदरा सूरजपुर- अमरपुर- लालन-खिरखिट- खिसलोनी खिरिया नयागांव (55 डे; लागत-110 करोड़ रुपए)

इसके साथ ही गुना के लिए अतिरिक्त फतेहगढ़ तिराहे पर फ्लाईओवर की मांग भी सिंधिया ने नितिन गडकरी से की है। इसे 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

नितिन गडकरी ने दे दी है स्वीकृति

वहीं, मीटिंज के दौरान परिवहन मंत्री ने इन प्रोजेक्ट्स को मौखिक स्वीकृति दे दी है। 1040 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स से गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में विकास की नई बयार बहेगी।

कोलकाता की घटना को लेकर एम्स भोपाल में नई व्यवस्था लागू

अब बिना अनुमति डॉक्टरों के ड्यूटी रूम में नहीं जा सकेंगे बाहरी

सिटी चीफ भोपाल।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद एम्स भोपाल ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम भोपाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल में अब बिना अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति महिला डॉक्टरों के ड्यूटी रूम में नहीं जा सकेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद एम्स प्रबंधन ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था बनाई है।

इसके तहत डॉक्टरों के रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) कार्ड बनाए जाएंगे। इसमें संबंधित डॉक्टर का थंब या फेस कार्ड जनरेट किया जाएगा, जिसकी मदद से डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम को खोल सकेगा। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के ड्यूटी रूम में आना भी चाहता है तो इसके लिए डॉक्टर की आरएफआईडी की आवश्यकता पड़ेगी। यह यहां के 200 से ज्यादा डॉक्टरों को दिए जाएंगे। इसके अलावा एम्स प्रबंधन कैमरों की संख्या भी बढ़ाने के साथ अन्य सुविधाएं भी शुरू करने जा रहा है। बता दें कि कोलकाता में हुई घटना के बाद पूरे देशभर के डॉक्टर पीड़िता को न्याय दिलाने और सुरक्षा की मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। हालांकि प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन एम्स के रेजिडेंट डाक्टर अभी भी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और लगातार

हड़ताल कर रहे हैं। इसमें एम्स प्रबंधन ने उनकी कुछ मांगों को पूरा कर दिया है।

परिसर में लगेंगे अलार्म

एम्स भोपाल परिसर में ऐसे क्षेत्रों को भी चिह्नित किया जाएगा, जो संदिग्ध क्षेत्र में आते हैं, यहां करीब 150 से अधिक अलार्म लगाए जाएंगे। यह तेज आवाज और सेंसर आधारित होगा, इसमें अगर किसी डॉक्टर पर आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो यह अलार्म स्वत: बजने लगेगा। इस पर डॉक्टर की सुरक्षा की जा सकेगी। हालांकि अभी इसे लेकर अभी प्रबंधन ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा है कि यह किस तरह काम करेगा। इसके अलावा परिसर के अंदर और बाहर अंधेरी जगह पर पर्याप्त रोशनी की सुविधा भी रहेगी।

महिला गार्डों की बढ़ेगी संख्या

महिला मरीज और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए एम्स प्रबंधन महिला गार्डों की तैनाती करेगा। अभी एम्स में गिनी-चुनी महिला गार्ड हैं, इसलिए इसके लिए उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यह गार्ड सुरक्षा के लिहाज से भर्ती होने वाली महिला मरीजों की बारीकी से जांच करेंगी। जिसमें वह देखेंगी कि उक्त मरीज ने किसी प्रकार का हथियार जैसी चीज तो साथ में नहीं रखी है।

हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है कैदी

सेंट्रल जेल में प्रहरी ने कैदी को मारा थप्पड़, कान का पर्दा फटा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। सेंट्रल जेल भोपाल में जेल प्रहरी द्वारा एक बंदी के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। जेल प्रहरी के थप्पड़ मारने के बाद बंदी के कान में असहनीय दर्द शुरू हो गया था। हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान उसके कान का पर्दा फटने की बात सामने आई।

मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद जेल अधीक्षक ने आरोपित जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसकी विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इस जांच के बाद जेल प्रहरी के खिलाफ गांधी नगर थाना पुलिस में एफआइआर भी दर्ज कराई जा सकती है। जेल से मिली जानकारी के मुताबिक मूलत: ग्राम पठाकोड़ी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन निवासी 36 वर्षीय रेवाराम पुत्र भावसिंह को हत्या के मामले में जुलाई 2015 में विचाराधीन कैदी के रूप में सेंट्रल जेल भेजा गया था। हत्या के मामले में सात मई 2016 को दोषी पाते हुए अदालत

ने रेवाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह सजा काट रहा है।

कैदी की बिगड़ गई थी हालत

18 अगस्त को किसी बात को लेकर जेल प्रहरी मनीष शेखर ने रेवाराम के साथ जेल में मारपीट करना शुरू कर दी। इसी दौरान प्रहरी ने कान में जोरदार थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद रेवाराम के कान में असहनीय दर्द शुरू हो गया। हालत बिगड़ती देख उसे उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया। वहां जांच के दौरान डाक्टर ने गंभीर चोट लगने के कारण कान का पर्दा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी।

जेल उप अधीक्षक एमएस मरावी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने प्रहरी मनीष शेखर को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय जांच पूरी होने पर जेल प्रहरी के खिलाफ थाने में मारपीट का केस भी दर्ज कराया जा सकता है। बंदी का उपचार कराया जा रहा है।

राजस्व वसूली का काम निजी हाथों में दिए जाने को लेकर असमंजस

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। नगर निगम भोपाल द्वारा राजस्व वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को सौंपा जाना है इसको लेकर पूर्व में किए किए प्रयोग विफल रहे है । ऐसे में एक बार फिर से इस काम को निजी एजेंसी को सौंपा जाए या नहीं इसको लेकर निगम प्रशासन में संशय है। लिहाजा महापौर परिषद की आगामी बैठक के एजेंडे में यह मुद्दा होगा या नहीं, इसको लेकर महापौर मालती राय से लेकर राजस्व प्रभारी जगदीश यादव सहित अधिकारी भी कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है।

राजस्व वसूली का काम निजी हाथों में सौंपने को लेकर नगर निगम का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। उसकी ओर से तीन बार यह कवायद की गई, लेकिन तीनों ही बार या तो एजेंसी काम छोड़कर भाग गई या अपेक्षित नतीजे न मिलने पर राजस्व वसूली का काम उनसे वापस ले लिया गया। इस मामले को लेकर इस माह के अंत या सितंबर की शुरूआत में महापौर मालती राय महापौर परिषद की बैठक करेंगी, जिसमें एजेंडा तय होगा। हालांकि वसूली का काम निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर संशय है, लिहाजा इस बार भी शायद यह प्रस्ताव न आए। वहीं निगम के जानकारों की मानें तो इस बार भी यदि प्रस्ताव आया तो इस प्रयोग के विफल होने की पूरी संभावनाएं है।

जल्द होगी परिषद की बैठक

उधर नगर निगम परिषद की बैठक सितंबर माह के पहले सप्ताह में संभावित है। निगम के नियमानुसार हर दो माह बाद परिषद की बैठक बुलाना अनिवार्य है। जल्द ही मेयर मालती राय और निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जल्द ही परिषद की बैठक की तारीख तय करेंगे। सूत्र बताते है कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में बैठक होने की संभावनाएं हैं।

इनका कहना है

इस मामले को एमआईसी में रखा जाएगा। सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। पूर्व के अनुभवों को भी ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

जॉर्ज कुरियन ने राज्य सभा के लिए जमा किया नामांकन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मप्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई रिक्त हुई सीट के लिए केरल के जॉर्ज कुरियन ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। वह दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ मप्र विधानसभा परिसर में रिटर्निंग अफसर के कक्ष में पहुंचे और पर्चा भरा।

इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, सत्यनारायण जटिया, मंत्री तुलसीराम सिलावट, उदय प्रताप सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

नामांकन दाखिल करने के बाद मीडियाकर्मियों से चर्चा में जॉर्ज कुरियन ने कहा कि पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, इसके लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताता हूं। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारा प्रतिनिधित्व अब और बढ़ जाएगा।

केरल से हमारा संबंध बहुत पुराना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि तमिलनाडु के बाद अब केरल से भी हमारा प्रतिनिधित्व होगा। गौरतलब है कि राज्य सभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। एक दिन पहले मंगलवार को भाजपा ने अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के साथ मप्र से जॉर्ज कुरियन के नाम की घोषणा की थी।

सीएम ने किया स्वागत, दी बधाई

जॉर्ज कुरियन आज सुबह एयर इंडिया की नियमित फ्लाइट से भोपाल पहुंचे। राजा भोज एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वीडी शर्मा के साथ कुरियन मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी।

गौरतलब है कि कि मप्र विधानसभा में दलीय स्थिति के आधार पर इस सीट से भाजपा उम्मीदवार का चुना जाना निश्चित है। इसी कारण कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। गौरतलब है कि पिछले आम चुनाव में गुना लोकसभा सीट से चुने जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।

लिहाजा इस सीट पर उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए उप चुनाव हो रहा है। कुरियन को अप्रैल 2026 तक का कार्यकाल मिलेगा। वह दक्षिण भारत से एल मुरुगन के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं, जिन्हें मप्र से राज्य सभा में भेजा जा रहा है।

प्रथम नेशनल स्पेस डे पर खास : बच्चों के बीच एस्ट्रोनॉट के रूप में पहुंच सारिका ने बताई भारतीय स्पेस की सफलता

बच्चों ने जाना चंद्रमा का शिवशक्ति स्टेशन और विक्रम-प्रज्ञान की सफलता

सिटी चीफ भोपाल।

एक साल पहले 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग करके यह सफलता प्राप्त करने वाला भारत पहला देश बन गया। इस सफलता को मनाने के लिए भारत सरकार ने इसे नेशनल स्पेस डे घोषित किया है। इस पहले नेशनल स्पेस डे के अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी जानकारी देने के लिए नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू एस्ट्रोनॉट के रूप में पहुंच रही हैं। वे ग्रामीण तथा जनजाति बहुल गांवों में पहुंचकर देश की वैज्ञानिक सफलता को बता रही हैं। साथ ही बच्चों को इसरो की सफलता की जानकारी दे रही हैं।

सारिका ने बताया कि चंद्रमा पर लैंडिंग साइट को शिवशक्ति स्टेशन नाम दिया गया है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से निकलकर प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह और वातावरण, थर्मो फिजिकल विशेषताएं, प्लाज्मा वातावरण, एलीमेंट कंपोजीशन और भूकंपन्न का अध्ययन किया इसमें रोवर मोबेलिटी को भी देखा गया।

सारिका ने बताया कि स्पेस डे की थीम 'चंद्रमा को छूते हुये जीवन को छूना = भारत की अंतरिक्ष गाथा' रखी गई है।

चंद्रयान-4 मिशन में चंद्रमा के पत्थरों और मिटटी को पृथ्वी पर लाने का लक्ष्य

आगामी स्पेस कार्यक्रमों की जानकारी देते हुये सारिका ने बताया कि जल्दी ही गगनयान के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को तीन दिन के मिशन में 400 किमी ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। ये यात्री वापसी में समुद्र में सुरक्षित रूप से लैंड करेंगे। इसके बाद चंद्रयान-4 मिशन में चंद्रमा के पत्थरों और मिटटी को पृथ्वी पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान को लांच करना शामिल होगा। सारिका ने संदेश दिया कि तैयार हो जाएं चंदामामा तक पृथ्वी का संदेश ले जाने वाली भारतीय सफलता का जश्न मनाने पहले नेशनल स्पेस डे के रूप में।

सम्पादकीय

क्या पीएम मोदी रुकवाएंगे रूस-यूक्रेन की जंग?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी यूक्रेन संकट के समाधान पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ विचार-विमर्श करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन में स्थिति गंभीर बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते एक साल से भी ज्यादा समय से जंग चल रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी यूक्रेन संकट के समाधान पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ विचार-विमर्श करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन में स्थिति गंभीर बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते एक साल से भी ज्यादा समय से जंग चल रही है। इससे भारत के हित प्रभावित होने की आशंका है। पीएम मोदी का यह यूक्रेन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। इसमें रक्षा, आर्थिक संबंध, साइंस और अत्याधुनिक तकनीक शामिल हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के 1000 किमी के इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं रूसी सेना अब चारों ओर से यूक्रेन की सेना को घेर रही है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पीएम मोदी कीव की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। दरअसल, भारत ने सोवयित जमाने में एक कंपनी से कई ऐसे हथियार खरीदे थे जो अब आधुनिक जमाने में यूक्रेन में है। भारत अभी भी यूक्रेन से जिन रक्षा उपकरणों को खरीदता है, उसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टर्बाइन और एएन 32 मालवाहक एयरक्राफ्ट शामिल है जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स करती है। यही वजह है कि भारत के लिए यह फायदे का सौदा है कि वह यूक्रेन के साथ अपने मजबूत रक्षा संबंध बरकरार रखे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सरकारी कंपनी जोर्या माशप्रोइक्ट भारत की निजी सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर भारतीय युद्धपोतों के लिए संयुक्त रूप से गैस टर्बाइन बनाने के लिए बात कर रही है। यही नहीं भारत और यूक्रेन विमान और प्लेन के इंजन भारत में बनाने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। भारत में अगर संयुक्त रूप से इंजन बनाए जाते हैं तो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को आसानी से गैस टर्बाइन मिल सकेगा। वहीं भारतीय वायुसेना की बात करें तो उसके पास कुल 105 एएन 32 विमान हैं जो मध्यम क्षमता के रणनीतिक ट्रांसपोर्ट विमान माने जाते हैं। इस विमान की खासियत यह है कि यह बहुत गर्म माहौल में पहाड़ी इलाके में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना एएन-32 विमान पर बहुत ज्यादा निर्भर है जो उत्तरी सीमा पर तैनात सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा एयर कार्गो ड्राप, पैरा ड्राप और मेडिकल इमरजेंसी शामिल है। भारत ने साल 2009 में यूक्रेन की कंपनी के साथ 40 करोड़ डॉलर का समझौता किया था ताकि एएन 32 विमानों को अपग्रेड किया जा सके। इससे ये विमान 40 और वर्षों के लिए काम कर सकेंगे। यह अपग्रेड करने का काम अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। भारतीय वायुसेना के एन 32 विमानों में यूक्रेन के दो इवचेंको प्रोग्रेस टर्बोप्रॉप इंजन लगे हुए हैं। इस इंजन को यूक्रेन के जापोरीझझाया में स्थित मोटर सिच कंपनी और पर्म इंजन प्लांट रूस में बनाया गया है। भारत अपने प्रोजेक्ट 11356एम के तहत गोवा शिपयार्ड में दो फ्रीगेट बना रहा है जो अब यूक्रेन के गैस टर्बाइन नहीं मुहैया करा पाने की वजह से अधर में लटक गया है। रूस इस युद्धपोत के लिए तकनीकी सहायता मुहैया करा रहा है। यूक्रेनी गैस टर्बाइन की वजह से भारतीय युद्धपोतों को ताकत मिलती है। इसके अलावा साल 2018 में भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत रूस ग्रिगोरोविच क्लास के दो फ्रीगेट नौसेना के लिए ले रहा है। साथ ही गोवा शिपयार्ड में भी दो और फ्रीगेट बनाया जाना है। रूस के इन युद्धपोतों पर यूक्रेन के गैस टर्बाइन लगने हैं। इस बीच साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन ने इन इंजन को देने से इंकार कर दिया था।

लेटरल एंट्री पर विपक्ष के हाथ लगी 'मास्टर की'

एक सवाल यह भी है कि बेशक सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हर नियुक्ति केवल आरक्षण के हिसाब से होगी तो लेटरल नियुक्ति का उद्देश्य भी केवल नौकरी देने तक, भले ही वह सीमित अवधि के लिए हो, रह जाएगा। हाल में जो विवाद छिड़ा उसका सीधा लक्ष्य वोट बैंक है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही संविधान और आरक्षण की टेक को इतनी बारीकी से पकड़ा हुआ है कि भाजपा और मोदी सरकार उसकी पकड़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं।

सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर मचे बवाल के तीन दिन बाद ही इस मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा यू-टर्न लेने का मतलब साफ है कि हाल के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस के हाथ संविधान और आरक्षण की वो 'मास्टर की' लग गई है, जो मोदी सरकार की किसी भी पहल की भ्रूण हत्या कर सकती है।

लेटरल एंट्री मामले में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर यह कहकर सवाल उठाए थे कि बिना आरक्षण प्रावधान से पिछले दरवाजे से यह सीधी भर्ती इसका सूचक है कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और आरक्षण को न मानना संविधान खत्म करने जैसा है। गौरतलब बात यह है कि मोदी सरकार ने लेटरल भर्तियां 2018 में ही शुरू कर दी थीं। लेकिन तब विपक्ष की और से भी इसका खास विरोध नहीं हुआ था, जो अब हो रहा है।

सरकार इसका न तो कोई ठोस तोड़ खोज पा रही है और न ही विपक्ष के हमलों का पुरजोर राजनीतिक जवाब दे पा रही है। राहुल गांधी के अलावा खुद एनडीए के दो घटकों जद यू और लोक जन शक्ति पार्टी ने भी इन नियुक्तियों का सार्वजनिक रूप से विरोध कर दिया। हालांकि, सरकार में शामिल एक और घटक टीडीपी ने इसका समर्थन किया। बावजूद इसके सरकार ने संविधान और आरक्षण के मुद्दों को लेकर आसन्न राजनीतिक खतरों को भांपा और अपनी बात पर अड़े रहने की जगह बैक फुट पर जाना ही बेहतर समझा।

यह भी साफ हुआ कि एनडीए में लेटरल एंट्री पर एकमत नहीं है। कहने को मोदी कैबिनेट के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कमजोर पलटवार जरूर किया कि लेटरल एंट्री का विचार सबसे पहले कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में ही आया था। लेकिन अब कांग्रेस ही इसका विरोध रही है।

दरसअल, मोदी 1.0 व 2.0 के ठीक उलट मोदी 3.0 में सरकार को कोर मुद्दों पर बार- बार बैक फुट पर जाना पड़ रहा है। मसलन वक्फ बिल सरकार ने संसद में पेश तो किया लेकिन व्यापक विरोध के चलते उसे जेपीसी के पास भेजना पड़ा। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे भी भाजपा की रणनीति देख रहे हैं। इसी तरह समान नागरिक संहिता (जिसे अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेक्युलर सिविल कोड कह रहे हैं), के मानसून सत्र में संसद में पेश किए जाने की चर्चा थी। लेकिन वह भी नहीं हो पाया।

अब लेटरल एंट्री के सवाल पर भी सरकार ने यू टर्न लेकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे यह आशंका सही साबित हो रही है कि एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता संचालन के पिच पर उस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी नहीं कर पाएगी, जैसी कि वो पूर्व के दो कार्यकालों में कर सकी थी। दूसरे कार्यकाल में केवल तीन विवादित कृषि कानूनों का मुद्दा ही ऐसा था, जब मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन अब यह बार बार होता दिख रहा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री की विधिवत शुरुआत मोदी 1.0 में 2018 में हुई। तब पहली बार 9 विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों पर सवाल तो तब भी उठे थे, लेकिन कोई राजनीतिक बवाल नहीं मचा। इन 9 विशेषज्ञों का चयन भी यूपीएससी ने 6077 आवेदनों में से किया था। इसमें किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये नियुक्तियां 3 से 5 साल तक के लिए की गई थीं। इनका कोई अलग से कैडर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से हटना था।

बीते 6 सालो में हुई लेटरल एंट्रियों के जरिये भर्ती हुए विषय विशेषज्ञों का क्या परफार्मेंस रहा, प्रशासन को और कार्यक्षम बनाने में उनकी क्या भूमिका रही, यह प्रयोग कितना सफल और कितना जरूरी समझा गया, आईएएस के एक सुगठित और जटिल जाल में लेटरल एंट्री छाप अधिकारी कितनी आजादी से काम कर पाए, उनकी काबिलियत का सरकारी तंत्र में कितना सदुपयोग हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

फिर भी सरकार ने ये भर्तियां जारी रखी हैं, इसका अर्थ यही मानें कि वह इन लेटरल एंट्री नौकरशाहों के काम से संतुष्ट रही होगी। लेकिन तब और अब में राजनीतिक फर्क यह है कि जब लेटरल एंट्री सूत्र पर अमल शुरू हुआ तब इसे सरकार में कारपोरेट मानसिकता की सीधी एंट्री और पूंजीवाद के फैलते जाल के रूप में देखा गया था, जिसकी प्राथमिकताएं लोकसेवक से अलग और एक संस्थान को हर हाल में मुनाफे में चलाने के आग्रह से निर्देशित होती हैं।

'जनसेवा' वहां केवल पैसे के बदले दी जाने वाली 'सर्विस' और तकनीकी गुणवत्ता ग्राहक को संतुष्ट के करने के भाव से तय होती है ताकि उपभोक्ता कंपनी से न सिर्फ जुड़ा रहे बल्कि बार उसकी सेवाएं लेता रहे। जबकि एक लोकसेवक संविधान और चुनी हुई सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। लोक प्रशासन का अपना एक विशाल और बेहद जटिल तंत्र है, जो कई गुणों और दोषों से भरा हुआ है। इसमें भी चंद लोग नवाचारी निकल आते हैं। कई भ्रष्टाचार को ही 'लोकसेवा' मान लेते हैं तो ज्यादातर अपनी गर्दन बचाकर नौकरी करते जाने को ही लोकसेवा मानते हैं।

इस तंत्र में प्रतिस्पर्द्धा पेशेवर अथवा गुणवत्ता के बजाए मलाईदार पोस्ट हथियाने और राजनीतिक आकाओं को खुश रखने की ज्यादा होती है। दूसरी तरफ कारपोरेट क्षेत्र से आने वाले विशेषज्ञ तुलनात्मक रूप से ज्यादा आजादी ,कड़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा और न्यूनतम जवाबदेही के माहौल के काम करने आदी होते हैं। वहां प्रतिस्पर्द्धा अपना 'बेस्ट' देने के आग्रह से ज्यादा संचालित होती हैं। हालांकि, व्यवसायगत चालाकियां और दुरभिसंधियों का बोलबाला वहां भी है, लेकिन मालिक को साधकर काफी कुछ साधा जा सकता है।

ऐसे में लेटरल एंट्री भारत के जटिल प्रशासनिक तंत्र में कितनी कारगर है, यह अध्ययन का विषय है। ऐसे लोग एक रूढ़िवादी और जड़ मानसिकता भरे तंत्र में कुछ नया करना चाहें भी तो उनके पास समय बहुत कम होता है। महज 3 या 5 साल की नौकरी में कोई बड़ा नवाचार वो कर पाते होंगें, कहना मुश्किल है। शीर्ष पदों पर तो यह फिर भी संभव है, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी और निदेशक पदों पर यह ज्यादा मुश्किल है, जहां आदेश का ठीक से पालन कराना ही पहला काम है।

बहरहाल विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है, वह राजनीतिक रूप से अहम इसलिए है, क्योंकि यूपीएससी के हालिया विज्ञापन में आहूत 45 लेटरल भर्तियों में जातिवार आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था। जबकि सरकार की यह संवैधानिक बाध्यता है। क्या यूपीएससी में बैठे लोगों को नियम- कायदों का पता नहीं था? या केवल बदले हालात में राजनीतिक टेस्टिंग के मकसद से यह विज्ञापन जारी किया गया?

हाल के वर्षों में नियम-कायदों को दरकिनार कर सरकारी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने की घटनाएं बढ़ी हैं। अमूमन हर विज्ञापन पर बवाल मचता दिखता है। मामला कोर्ट में जाता है। वहां से डांट पड़ती है। कहना कठिन है कि ऐसा जानबूझकर हो रहा है या फिर जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो अज्ञानी हैं।

यह भी सही है कि नौकरशाही में सुधार की मंशा से लेटरल एंट्री का विचार काफी पुराना है। बुनियादी तौर पर इसमें कुछ गलत भी हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि निजी क्षेत्र से आए विषय विशेषज्ञ ब्यूरोक्रेसी की जड़ता में नवाचार और दूरुत गति की लहरें पैदा कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लेटरल एंट्री का समर्थन किया। खुद कांग्रेस ने भी समय समय पर सिविल सेवकों के इतर प्रतिभाशाली लोगों को सीधे सरकार में नियुक्तियां दी थीं, वो भी एक तरह लेटरल एंट्री ही थी। लेकिन कांग्रेस इसे संस्थागत रूप देने का साहस नहीं जुटा पाई, जो बाद में मोदी सरकार ने किया।

अब वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। यहां एक सवाल यह भी है कि बेशक सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हर नियुक्ति केवल आरक्षण के हिसाब से होगी तो लेटरल नियुक्ति का उद्देश्य भी केवल नौकरी देने तक, भले ही वह सीमित अवधि के लिए हो, रह जाएगा। हाल में जो विवाद छिड़ा उसका सीधा लक्ष्य वोट बैंक है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही संविधान और आरक्षण की टेक को इतनी बारीकी से पकड़ा हुआ है कि भाजपा और मोदी सरकार उसकी पकड़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं।

सरकार और पार्टी यह दमदारी से कह ही नहीं पा रही है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, वो देशहित में है और सही है। क्योंकि आरक्षण की बात आते ही भाजपा को अपना ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट बैंक खिसकने का डर है। वैसे भी भाजपा लोकसभा चुनाव के दूध की जली है। लिहाजा ऐसा कोई भी परसेप्शन जो उसके संविधान खत्म करने या आरक्षण समाप्त करने का गढ़ता हो, वह छुईमुई हो जाती है। लेटरल एंट्री के मामले में बैक फुट पर जाना इसी का परिचायक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह सरकार पांच साल तक कैसे चलेगी?

चीन खुद एक वैश्विक समस्या, फिर भी दुनियाभर के बाजारों पर ड्रैगन का दबदबा

वेनेजुएला के भूतपूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने 2000 के दशक में अपने देश का आर्थिक भविष्य उभरते चीन के ऊपर दांव पर लगा दिया, इससे उसे अरबों डॉलर का निवेश मिला और तेल सौदों के लिए कर्ज भी। शुरुआत में इससे फायदा हुआ। चीन ने जमकर वेनेजुएला के तेल का उपभोग किया और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया। लेकिन 2010 के दशक में तेल की कीमतें गिर गईं और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ चीन की ओर से तेल की मांग भी घट गई। नतीजतन वेनेजुएला के तेल निर्यात का राजस्व 2016 में घटकर 22 अरब डॉलर रह गया। उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। लोग कचरे के ढेर में भोजन तलाशने लगे, अस्पतालों में दवाओं की कमी थी और अपराध बढ़ गए थे। तब से, लगभग 80 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं। चीन ने वेनेजुएला को नए ऋण देने से मना कर दिया, जिससे वहां अधूरी परियोजनाओं का ढेर लग गया। चीन पर वेनेजुएला की अत्यधिक निर्भरता एक चेतावनी थी, जिसकी दुनिया ने अनदेखी की। चीन के उदय से लाभान्वित दर्जनों अन्य देश अब वित्तीय संकट और ऋण न चुका पाने के जोखिम में फंसे हैं, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था ठहर गई है। फिर भी चीन ऋण राहत देने से इन्कार कर रहा है और संरक्षणवादी गतिविधियों पर दोगुना जोर दे रहा है, जबकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त करने और नई शुरुआत के लिए सुधार करने चाहिए। यह बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था के जादुई गुब्बारे का दूसरा पहलू है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया को एक रक्षक की जरूरत थी और चीन ने वह भूमिका निभाई। इसका सकारात्मक प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया। वर्ष 2008 से 2021 तक चीन ने वैश्विक विकास में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। विकासशील देशों ने खुद को चीन से जोड़ा, और चीन दुनिया के अधिकांश देशों का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। वेनेजुएला की तरह कई देशों ने पाया कि तेजी से बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था उनके वस्तु निर्यात के लिए एक आकर्षक बाजार है, और उन्होंने उसमें भारी निवेश किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सुस्ती का सामना करना पड़ा। चीन ने विभिन्न देशों को दस खरब डॉलर से ज्यादा का ऋण दिया है, जिसका बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों द्वारा बीआरआई (बेल्ट?एंड रोड इनीशिएटिव) के तहत बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचे के लिए है। मगर चीन की तेजी टिकाऊ नहीं थी।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उद्यमशीलता को दबाया, सुधार का विरोध किया और अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया को उकसाया। शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद चीन के आर्थिक विकास में काफी कमी आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुश्किल से ही बढ़ रहा है। हालांकि चीन ने लगातार बाहरी स्रोतों के अनुमान से ज्यादा विकास का दावा किया है।

जान बचाने वाले कितने सुरक्षित, कोलकाता की घटना ने चिकित्सा पेशे की परिस्थितियों पर खड़े किये सवाल

अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही जूनियर डॉक्टर की नौ अगस्त को कोलकाता में एक क्रूर घटना में जघन्य हत्या कर दी गई। इससे पूरे राष्ट्र का जनमानस हिल गया है। इसने एक बार पुन: निर्भया हत्याकांड की याद ताजा कर दी, लेकिन यह घटना तो उससे भी कहीं यादा वीभत्स है। निर्भया की हत्या राह चलती बस में यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कीगई थी, लेकिन हाल में घटित घटना को अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान पर अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम से प्रतीत होता है कि यह पूर्व नियोजित था।

अस्पताल के अंदर कार्यरत चिकित्सक की कार्यावधि के दौरान की गई हत्या जूनियर एवं प्रशिक्षु डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के जरिये राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने में लगी हैं और चिकित्सक के प्रति हिंसा का विषय नेपथ्य में चला गया है। विभिन्न अवसरों पर चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसक वारदात के विरोध में चिकित्सक संगठन अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन यादातर अवसरों पर ठंडे छींटे देकर आंदोलन को शांत कर दिया जाता है। चिकित्सकों से सेवा की तो पूर्ण अपेक्षा रखी जाती है, किंतु उनकी सुरक्षा के प्रति जवाबदेही के लिए बनाया जाने वाला कानून वर्ष 2022 से लंबित है। उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा कानून बनाने के बावजूद स्वास्थ्य राय सूची का विषय होने के कारण संपूर्ण दारोमदार रायों पर ही आ जाता है। कई रायों ने विभिन्न अवसरों पर आंदोलनरत चिकित्सकों को शांत करने के लिए कानून तो बना दिए, लेकिन वे धरातल पर नहीं उतरे। जैसे राजस्थान में कानून तो वर्ष 2008 में बन गया था, किंतु प्रभावी क्रियान्वयन डॉ. अर्चना शर्मा द्वारा दबाव में की गई आत्महत्या के उपरांत वर्ष 2022 में तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पश्चात ही हो पाया है।

कोलकाता की घटना ने चिकित्सकों विशेष तौर पर दिन-रात सेवारत सहयोगी चिकित्सकों की कार्य परिस्थितियों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। चिंतनीय है कि जिनके हाथों में जीवन बचाने का दायित्व सौंपा जा रहा है, उनके पास ठीक से उठने-बैठने, आराम करने और निवृत्त होने की उचित व्यवस्था भी नहीं रहती। चिकित्सा के व्यावसायीकरण और विशेष तौर पर कॉरपोरेट संस्कृति में ढलने से वहां कार्यरत चिकित्साकर्मी भी एक सामान्य कर्मी बन कर रह गए हैं।

मरीजों के बोझ में दबे सरकारी चिकित्सा संस्थानों का तो हाल और भी चिंताजनक है। विभिन्न रायों द्वारा नर्सिंग होम या अस्पताल की स्थापना के मानक तय करने को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किए गए हैं, जिनमें ड्यूटी डॉक्टर हेतु कक्ष एवं शौचालय का भी मानक रखा गया है, किंतु वह अत्यंत अल्प है, जिसमें अनेक चुनौतियां रहती हैं। हाल की घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की पहल पर पुरुष व महिला प्रशिक्षु और ड्यूटी चिकित्सकों के लिए समुचित कक्ष की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन क्रियान्वयन का दायित्व तो राय सरकारों एवं चिकित्सा संस्थान संचालकों की नीयत पर है। एक ओर भारत सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की महत्वाकांक्षा के साथ तीव्र गति से कार्य कर रही है, वहीं चिकित्सक इस व्यवसाय के प्रति पुनर्विचार करने लगे हैं। इन सबके मूल में निरंतर असुरक्षा का भाव सबसे प्रमुख है। पूर्व में चिकित्सक का स्वप्न होता था कि अपनी अगली पीढ़ी को भी चिकित्सक बनाना, लेकिन विगत वर्षों में इस चलन में कमी आई है। इस कमी के पीछे जहां आर्थिक कारण एक पक्ष है, वहीं नित्य प्रति घटित होने वाली घटनाएं प्रमुख रूप से दोषी हैं।

भारत की शीर्ष संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि लगभग 83 प्रतिशत चिकित्सकव्यवसाय संबंधी तनाव में जीवनयापन करते हैं। लगभग 63 प्रतिशत को हिंसा का भय सताता रहता है, तो आधे चिकित्सकों के तनाव की मुख्य वजह हिंसक वारदात होती है। क्या तनावग्रस्त चिकित्सक से बेहतर इलाज की अपेक्षा की जा सकती है यदि चिकित्सक असुरक्षित महसूस करते रहे, तो संस्थान निर्मित होने के बावजूद सूने रह जाएंगे। चिकित्साकर्मियों के कार्य एवं आवास हेतु उपयुक्त व्यवस्था के अभाव के चलते ही चिकित्सक गांवों से विमुख हुए थे और अब शहरों सेभी मोह भंग हो रहा है।इस तरह के आघात चिकित्सा व्यवसाय के साथ जुड़े गौरव को भी समाप्त कर रहे हैं। लंबी अवधि तक एवं जटिल शिक्षण के पश्चात कार्यरत चिकित्सक को उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने में आमजन को भी सरोकार रखना होगा। जिस प्रकार चिकित्सक उनको स्वस्थ रखने का यत्न करते हैं, उसी प्रकार तनावमुक्त कार्यस्थल व्यवस्था हेतु स्वैछिक संगठनों समेत सभी को मुखर होना होगा।

16 सितंबर को भारतीय किसान संघ करेगा किसान शंखनाद रैली तहसील बैठक में हूवा निर्णय

हजारों किसान ट्रैक्टर बाइक लेकर रैली में रहेंगे उपस्थित किसानो को कृषि में होने वाली समस्याओं को लेकर जिला केंद्र पर दिया जाएगा चेतावनी ज्ञापन

शाजापुर भारतीय किसान संघ शाजापुर तहसील मासिक बैठक कृषि उपज मंडी शाजापुर में जिसमें भगवान बलराम भारत को मालिया अर्पण कर ध्वज लगाकर नारा जय घोष करते हुए बैठक में आगमी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई जिसमें 16 सितंबर को शाजापुर में प्रत्येक गांव से किसान साफा बांधकर 500 ट्रैक्टर बाइक लेकर वाहन रैली निकली जाएगी जिसमें प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस के रूप में तीन परत में ज्ञापन दिया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री एवं जिलाधीश महोदय के नाम का दिया जाता है जिसमें किसान संघ शाजापुर तहसील60 गांव में बलराम जयंती मनायगे जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई की उपस्थिति जिला अध्यक्ष सवाई सिंह जी सिसोदिया भारतीय किसान संघ ग्राम इकाई के बारे में जानकारी देते हुए बताएं कि 15 तारिक को प्रत्येक माह ग्राम समिति की बैठक जिले के 450 गांव में होना चाहिए ताकि हमें हमारे अधिकार हमारे कर्तव्य संगठन के बारे में गांव में किसानों को जानकारी हो सके और गांव की समस्याओं पर बैठकर विचार कर सामूहिक हल किया जा सके जिला मंत्री मुकेश पाटीदार द्वारा बताया गया कि जब तक भारतीय किसान संघ का छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपने आप को पूर्ण रूप से संगठन के प्रति कार्य का पालन करते हुए नियमित बैठक और किसानों को होने वाली समस्याओं और उनको जागरूक करने के बारे में विचार करे किसान के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा तब तक किसान संघ का जागरूक कार्यकर्ता नहीं बन पाएगा संगठन के कार्यकर्ता द्वारा किसान हित में जो भी कार्य किए जाते हैं वह उन कार्यों को अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर पूरा करे तहसील अध्यक्ष सतनारायण पाटीदार कहां की भारती किसान संघ तहसील शाहजहांपुर आने वाले 16 सितंबर को विशाल किसान शंखनाथ रैली का आयोजन करने वाला है जिसमें आप सभी किसानों के सहयोग जिले के सभी गांव से 500ट्रैक्टर एवं बाइक टंकी चौराहा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में आने वाले हैं जिसमें जिले के सभी गांव से किसान अपने गांव समिति में बैठक करके अपनी समस्या को ज्ञापन के रूप में टाइप कर 16 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में में उपस्थित होगे कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता जिला कोषाध्यक्ष ललित नागर बिजली आयाम एवं तहसील प्रभारी राज बहादुर गुर्जर जल आएं प्रमुख अनिल पाटीदार देश जिला प्रचार प्रसार प्रमुख भारत नहर तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण पाटीदार मंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर नगर अध्यक्ष जितेंद्र पाटीदार सर मंत्री राजेश पाटीदार तहसील उपाध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर उपाध्यक्ष दिनेश मंडलोई प्रवीण पाटीदार राजेश पाटीदार दिलीप प्रजापत राहुल पटेल विकास सिंह गुर्जर फूल सिंह गुर्जर अजय पाटीदार श्याम सुंदर सिंह एवं वीरेंद्र सिंह राजपूत एव सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे जानकारी तहसील मंत्री ज्ञानसिंह गुर्जर द्वारा दी गई।

स्वयं को पुलिस बताकर युवक का अपहरण करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

शाजापुर। स्वयं को पुलिस बताकर युवक का अपहरण करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अवंतीपुर बड़ोदिया थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी के नेतृत्व में पुलिस चौकी तिलावद एवं थाना अवंतीपुर बड़ोदिया की टीम द्वारा चौकी तिलावद क्षेत्र में हुई अपहरण की घटना अंजाम देने वाले आरोपियों को थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी की मदद से पकडने में कामयाबी मिली। पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त 2024 को फरियादिया श्यामूबाई पति रमेश खाती उम्र 55 साल निवासी अरनियाकला के द्वारा चौकी तिलावद पर सूचना दी गई थी उसका लडका पवन और वह ग्राम पुवडिया से बाइक से अपने गांव जा रहे थे, तभी ग्राम अरण्डिया-तिलावद जोड़ के बीच एक सफेद रंग की कार आई और बाइक के सामने आकर रूक गई। कार से दो व्यक्ति उतरे और स्वयं कां पुलिस बताकर पवन को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गए। सूचना पर चौकी तिलावद पर प्रकरण दर्ज किया। वहीं थाना प्रभारी अवंतीपुर बड़ोदिया द्वारा दो अलग-अलग टीम बनाकर अपहृत एवं आरोपियों की पतारसी हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा अन्य जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे, जमीनी स्तर की मुखबिरी तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर उक्त कार शिवपुरी से ग्वालियर जाने का पता चला, जिस पर थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी द्वारा तत्काल फोन पर थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी के थाना प्रभारी राजीव दुबे को उक्त घटना के बारे में बताया गया। थाना प्रभारी सुभाषपुरा द्वारा अपने स्टॉफ के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त गाड़ी को रोक कर अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस टीम के सुपुर्द किया गया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी, सउनि विजयसिंह राजपूत, सउनि रघुनाथसिंह राठौड़, प्रआर सुनिल, प्रआर विजय धनगर, आर लवकुश परमार, आर रवि वर्मा, आर कमलेश आवले, आर दिनेश वर्मा, आर अखिल वर्मा, आर गजेन्द्र खन्ना, आर गेहरबान अरड, शुभम, थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी थाना प्रभारी राजीव दुबे उनके स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

अवैध शराब परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के पास से हाथ भट्टी की लगभग 6000 रुपये कीमत 60 लीटर कच्ची शराब बरामद

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ

शाजापुर, अवैध शराब का परिवहन करने के मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मक्सी थाना प्रभारी भीमसिंह पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक के पास कालाभाटा रोड़ मक्सी से आरोपी सरिसनासिंह पारदी पिता भैय्या पारदी निवासी पारदीखेड़ा जिला उज्जैन को होंडा शाईन मोटर साइकिल बिना नंबर प्लेट से अवैध शराब का परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी के पास से हाथ भट्टी की कच्ची शराब 60 लीटर कीमत लगभग 6000 रुपये बरामद की गई। साथ ही बाइक को भी जब्त किया गया। आरोपी से बाइक और अवैध शराब कहां से कहां ले जाई जा रही थी इसको लेकर पूछताछ की जा रही है।

मानवीय मूल्यों का जीवंत बोध है जनजातीय संस्कृति एवं संस्कृति

नीमच-हू.. आज विकास की इस घुड़दौड़ ने मानवीय मूल्यों और अपने अतीत में व्यतीत किए हुए उन क्षणों को भूलता जा रहा है। किसी भी समाज का अतीत बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चेतना का संचार और आत्म गौरव की प्रतिष्ठा का विकास उसी से होता है। इसका तात्पर्य नहीं लिया जाना चाहिए ,शुद्ध अतीतवादी होने में तार्किक एकता नहीं हो सकती है और आधुनिक होने में भी तार्किकता नहीं हो सकती है। दोनों अपने समय और परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य द्वारा विकास के पैमाने को प्रतिष्ठित करने के लिए इन शब्दों को विभिन्न रूप से विलक्षण शब्दावली के साथ गढ़ा गया है ?। आदिवासी संस्कृति और समाज एक ऐसा समाज है जो अपने आत्म सम्मान और गौरव के लिए जाना जाता है एक ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन तो होता है ,परंतु वह सांस्कृतिक मूल्यों के साथ किसी भी रूप में समझौता नहीं करते। उनकी संस्कृति और सभ्यता की एक अमिट छाप जो किसी को भी आकर्षित करने , सीखने और सिखाने के लिए उत्प्रेरित करती है। परंतु यह भी विवाद का विषय है कि आखिरकार मुख्यधारा वाला व्यक्ति किसे माना जाए क्या आज पूंजीवादी और उपभोक्तावादी आधुनिकता की घुड़दौड़ वाली जिंदगी को मुख्यधारा वाला माना जाए ? या प्रकृति के सुरम्य वातावरण में निवास करने वाले उस मनुष्य को मुख्यधारा वाला व्यक्ति माना जाए जो सदैव कर्मशील और आत्मसम्मान से ऊर्जावान होता है। आज विकास के नाम पर उनके कई प्रकार की पहचानों और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है।आदिवासी समाज में कई प्रकार की रीति रिवाज और कथाएं प्रचलित होती हैं, परंतु एक बार जो उन सबमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है ।वह है प्रकृति प्रेम। यद्यपि , आदिवासी समाज प्रकृति पर निर्भर है फिर भी वह प्रकृति का दोहन सिर्फ इतना करता है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी समस्या का सामना ना करना पड़े ??। शायद ! सतत विकास की प्रक्रिया आधुनिक मनुष्य ने उसी से सीखी होगी। उनका एक लंबा गौरव और इतिहास है ?। जिसमें उनके योगदान को स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद के समय के रूप में बस नहीं देख लेना चाहिए। संरक्षित संस्कृति और अपने मूल्यों से समझौता न करने वाले समाज के रूप में भी उन्हें देखे जाने की आवश्यकता है। आज तथाकथित मुख्यधारा वाली समाज यह सरकारें उनके विकास के लिए एवं विकसित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। यह तो उचित प्रतीत होता है परंतु उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और व्यापक संख्या में उनका पुनर्वास यहां नया प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है।

आनंद सागर सुरीश्वरजी की रथ यात्रा का नगर में हुआ मंगल प्रवेश

देश भर के 108 शहरों से निकाली जा रही रथ यात्रा पहुंची शाजापुर

भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ

शाजापुर। जैन शासन के प्रमुख आगम उद्धारक आचार्य भगवंत श्रीआनंद सागर सुरीश्वरजी महाराज की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देशभर के 108 प्रमुख शहरों से निकाली जा रही रथ यात्रा का 21 अगस्त बुधवार सुबह शाजापुर नगर में मंगल प्रवेश हुआ। समाज के मीडिया प्रभारी मंगल नाहर ने बताया कि मालव गौरव परम पूज्य श्रीनवरत्न सागर सुरीश्वरजी मसा के शिष्य आचार्य भगवंत विश्वरत्न सागर जी मसा की प्रेरणा से गुरुवर आनंदरत्न सागर जी मसा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उक्त रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो जयपुर से प्रारंभ होकर संपूर्ण भारतभर के 108 शहरों से होती हुई शाजापुर पहुंची। यह यात्रा शाजापुर नगर में प्रवेश के दौरान स्थानीय कृष्णा टॉकीज चौराहा से प्रारंभ होकर नई सडक़, आजाद चौक, कसेरा बाजार होते हुए ओसवाल सेरी स्थित जैन उपाश्रय पहुंचकर धर्म सभा के रूप में संपन्न हुई, जहां पर पूज्य आचार्य आनंद सागर सुरीश्वरजी द्वारा जैन शासन के ऊपर किए गए उपकारों का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश नवरत्न परिवार के व्यवस्थापक राजेश जैन नलखेड़ा तथा विधिकारक अमित जैन अकोदिया द्वारा उद्घोधन दिया गया। उन्होने बताया कि जिस प्रकार वैष्णव संप्रदाय में भागवत गीता एवं मुस्लिम संप्रदाय में कुरान का महत्व है, उसी प्रकार जिन शासन में आगम ग्रंथों का मुख्य महत्व है। आगम के 45 ग्रंथों में जैन शासन का सम्पूर्ण संसार समाहित है। इस दौरान सभी आगंतुक अतिथियों का श्री आदेश्वर जैन मूर्ति पूजक ट्रस्ट द्वारा बहुमान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाज के अध्यक्ष लोकेंद्र नारेलिया, सचिव सपन जैन, कोषाध्यक्ष प्रतीक जैन, वरिष्ठ समाजसेवी नरेंद्र कोठारी, सुरेश जैन, विनोद जैन, अनिल गोलेछा, महेश जैन, मनोज गोलेछा, आशुतोष चोपड़ा, अजय जैन, प्रेम बढेरा, राहुल जैन सहित अन्य समाजजन उपस्थित थे। नवरत्न परिवार अध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि यात्रा का समापन दिनांक 25 अगस्त को रतलाम में होगा।

कर्पूरी ठाकुर ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय सचिव बने वर्मा

मध्य प्रदेश गुजराती सेन समाज प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान समेत ईष्ट मित्रों ने हर्ष व्यक्त किया है

शाजापुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर श्रीवास द्वारा मध्यप्रदेश गुजराती सेन समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा शाजापुर को राष्ट्रीय संगठन सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन पर प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश गुजराती सेन समाज अशोक चौहान, सुभाष वर्मा, संतोष वर्मा, स्मिता सोलंकी, जगदीश देवड़ा, बाबूलाल अंबोदिया, अर्जुन वर्मा सहित ईष्ट मित्रों ने हर्ष व्यक्त किया है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शहर में निकाली रैली

भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ शाजापुर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले को लेकर देशभर में अनुसूचित जाति-जनजाति के समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। इसीको लेकर बुधवार को विरोध स्वरूप भारत बंद का आह्वान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा किया गया और शाजापुर में बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खुले रखे तो वहीं कुछने स्वत- ही दुकानों को बंद रखकर आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति संघर्ष मोर्चा के द्वारा शहर में रैली निकाली गई।

भाई-बहन के अटूट बंधन रक्षा बंधन पर...

बहन ने भाई कि रक्षा हेतु कलाई पर बांधी राखी

लकेश पंचेश्वर। सिटी चीफ

लालबर्रा, प्रतिवर्षानुसार मनाया जाने वाला रक्षा बंधन पर्व इस वर्ष भी सादगी के साथ 19 अगस्त को मनाया गया बहनें अपने भाइयों को राखी बांधी तथा उनकी रक्षा कि कामना कि है।वहीं हम आपको अवगत करा देवें कि सावन माह के अंतिम पड़ाव पर यह पर्व हर साल आता है यह पर्व को सभी समुदाय के लोग वर्षों से मनाते हुए आ रहे है वहीं रक्षा बंधन को लेकर बहनों में खासी उत्सुकता रहती है भाई भी उत्साहित रहते हैं रक्षा बंधन पर्व को लेकर बहनें दूर दूर से अपने भाईयों को राखी बांधने पहुंचती हैं। वहीं बहन भी हाथों में मेहंदी लगाये हुए सज-धजकर कर भाई कि कलाई में राखी बांधते हुए तिलक लगाकर आरती उतारकर मिठाई खिलाते हुए आशीर्वाद देती है तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि मेरा भाई सलामत रहे हमेशा खुश रहे तथा भाई भी बहन से आशीर्वाद लेकर ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे हैं उसे किसी प्रकार कि बाधा ना आये जहां भी रहे खुशहाल रहे इस वजह से यह पर्व मनाते हुए आ रहे हैं लेकिन इस वर्ष धार्मिक मान्यता अनुसार 19 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद मनाया गया तथा कुछ लोगों ने 20 अगस्त को भी मनायें है यह भाई-बहनों का अटूट बंधन का पर्व है। जानकारी अनुसार एक माह तक चलने वाला सावन माह कि समाप्ति होती है तथा साल के पहले पर्व कि शुरुआत होती है इसके बाद सभी पर्व प्रारंभ होते हैं। वहीं बदलते परिवेश में जो भाई बहन काफी दूर रहते हैं वह आनलाइन ही राखी पहुंचा देते हैं। तथा बच्चें बहुत उत्साहित नजर आये है।

आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चे के आव्हान पर लालबर्रा बंद पूर्णतः सफल

संयुक्त मोर्चे ने व्यापारियों व दुकानदारों का जताया आभार व सौंपा ज्ञापन।

थमें रहे बसों के पहिये यातायात हुआ प्रभावित,पुलिस कि रही पैनी नजर

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ

लालबर्रा आरक्षण में क्रिमिलेयर के खिलाफ आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का असर बालाघाट जिले सहित लालबर्रा में भी देखने को मिला। मुख्यालय के जिन बाजारों में सुबह से ही हर दिन चहल-पहल दिखाई देती थी। वहां बंद आंदोलन के चलते सन्नाटा पसरा रहा। वाहनों के पहिए जाम हो गए। दुकानों में दिन भर ताले लटके रहें।आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए लालबर्रा बंद को बसपा सहित अन्य दलों और चैंबर ने अपना समर्थन दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज,अपने हक और अधिकार के लिए बुधवार को सड़क पर है। आंदोलनकारियों ने मांग की हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने अध्यादेश लाए। इसके अलावा भी हमारे कई और अन्य मांगे है, जिसको लेकर आंदोलनकारी सड़क पर हैं। वहीं आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने पर लालबर्रा पुलिस बल जगह-जगह पर तैनात रहे है। आंदोलनकारीयों ने मुख्यालय में रैली की जो यह रैली कार्यक्रम स्थल से सिवनी रोड़ मजार पहुंची तथा वहां से पुन: यह तहसील कार्यालय पहुंची वहां पर तहसीलदार महोदय को माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार,प्रधानमंत्री भारत सरकार, कानून मंत्री भारत सरकार, माननीय चीफ जस्टिस आंफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली व माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग नई दुनिया के नाम ज्ञापन पत्र सौंपे हैं ततपश्चात यह रैली कार्यक्रम स्थल में पहुंची जहां सभा का आयोजन किया गया।

थमें रहे बसों के पहिये यातायात व्यवस्था हुआ प्रभावित ज्ञात हो कि बंद से बसों के पहिये पुरी तरह से थम गए जिस वजह से यातायात पुरी तरह से प्रभावित हुआ लोगों को आवागमन में खासी असुविधा हुई वहीं थाना प्रभारी हेमंत नायक ने सुरक्षा कि जिम्मेदारी अपने कंधों पर स्वयं संभाली जिस वजह से क्षेत्र में कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। वहीं क्षेत्र में एमरजेंसी सेवाएं जैसे मेडिकल,दुग्ध डेयरी, पेट्रोल पंप चालू रहे तथा शासकीय कार्यलय पुरी तरह खुले रहे लेकिन आमजन नजर नहीं आये है लगभग 5 बजे के बाद एक एक करके दुकानें खुलना प्रारंभ हुई लेकिन कुछ ही दुकान खुली नजर आई।

कटनी में भारत बंद का दिखा मिला-जुला असर

सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फैसले के खिलाफ दलित-आदिवासी संगठनों की रैली और विरोध प्रदर्शन

सुनील यादव । सिटी चीफ

कटनी, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्धारा हाल ही में दिए गए निर्णय के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठनों द्धारा बुलाए गए भारत बंद का कटनी में ज्यादा असर तो नहीं रहा। बाजार में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। दलित और आदिवासी संगठनों के द्धारा शहर में रैली निकाल कर व्यापारियों से बंद की अपील की गई और इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर निर्णय को वापस लेने की मांग की गई।

रैली में शामिल दलित और आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता हाथों में झंडे बैनर लेकर निर्णय के विरूद्ध नारेबाजी कर रहे थे।गौरतलब है कि दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। और इनकी मांग है कि एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। भारत बंद का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।

कनकी ग्राम में नवविवाहिता जोड़ो ने भांवर फिरकर मनाया हरियाली का प्रतिक भुजली पर्व

भव्य शोभायात्रा निकालकर चौक-चौराहों का किया भ्रमण

लकेश पंचेश्वर। सिटी चीफ
लालबर्रा, नगर मुख्यालय से लगभग 15 किमी. दूर स्थित ग्राम पंचायत कनकी में भुजलिया का पर्व मंगलवार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर युवतियों व महिलाओं के द्वारा अपने घरों के आंगन में भुजलियों को निकालकर पूजा अर्चना करने के बाद सभी यूवतियों व महिलाओं द्वारा बालाघाट रोड़ मुख्य मार्ग पर एकत्रित होकर डीजे की धुन पर पारंपरिक गीतों के साथ थिरकते हुए भव्य शोभायात्रा निकाली गई जिसके बाद वैनगंगा नदी के तट पर और ग्राम के छोटे तालाब में आरती कर भुजलियों का विसर्जन किया गया। विदित हो की भुजलिया का यह पर्व पुरातनकाल से रक्षाबंधन के दूसरे दिन बड़ी धूमधाम के साथ मूलत अच्छी फसल, अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। भुजलिया पर्व की तैयारी नाग पंचमी से ही शुरू हो जाती है और इस पर्व पर घरों में गेहूं या जौ बोई जाती है जिन्हें भुजलियां कहा जाता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा इनकी पूजा अर्चना करके इन टोकरियो को जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है। जिसके बाद लोग अपने-अपने गांव मोहल्ले और नगरों में गणमान्य नागरिकों, परिवार के बड़े बुजुर्गों, महिलाओं को भुजलिया भेंटकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पर्व की शुभकामनाएं भी प्रेषित करते है।

सुख समृद्धि मंगलकामनाओं का प्रतीक है भुजली पर्व - **दुर्गाप्रसाद** प्रेस से चर्चा में कनकी के युवा सरपंच दुर्गाप्रसाद पगरवार ने कहा की हरियाली का प्रतिक भुजलियां पर्व प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भुजली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम के बड़ी संख्या में महिला, बहने, युवा, बुजुर्ग शामिल होकर पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते है खास तौर पर सर्वसमाज के नवविवाहिता जोड़े इस कार्यक्रम में शामिल होते है जिनका भांवर फिरने वाला कार्यक्रम होता है छोटे तालाब के पास जहां समस्त ग्रामीण उपस्थित होकर भव्य रैली के रुप में ग्राम की समुची गलियों का भ्रमण करते हुए भांवर फिरकर भुजलिया विसर्जित कर एक-दूसरे को भुजली देकर सुख समृद्धि की शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते है।आयोजित इस सफल कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायत कनकी के समस्त ग्रामीणजनों, युवा साथियों, महिलाओं व बुजुर्गो का मै हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

यह रहें शामिलआयोजित इस भव्य भुजली पर्व पर प्रमुख रुप से ग्राम के युवा सरपंच दुर्गा पगरवार, उपसरपंच राजकुमार भोयर, लखन कातूरे, अर्जुन लाल ठकरेले, मुकेश मंडलेकर, रेखलाल भोयर, मिताराम भोयर, राधेश्याम पिछोडे, रितेश शर्मा, कैलाश भोयर, दिलीप बांधे, अनवर बगमारे, सुनील भोयर, सहायक सचिव गणेश गौतम सहित हजारों की संख्या में महिला-बहने ग्रामीणजन शामिल रहें।

नहर में गिरे युवक के लिए देवदूत बनी उमरियापान पुलिस

थाना प्रभारी ने स्टाफ के साथ तत्काल पहुंचकर नहर मे डूबे युवक की बचाई जान

सुनील यादव । सिटी चीफ
कटनी, कटनी के उमरियापान थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदी मोड़ नहर में गिरे एक युवक की पुलिस ने समय पर पहुंचकर जान बचाई। जिसका एक वीडियो भी प्रकाश में आया है। दरअसल ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झिन्ना पिपरिया निवासी 37 वर्षीय संतोष पटेल पिता संत राम पटेल हरदी मोड़ नहर में अचानक गिर गया था और पानी गहरा होने के चलते डूब गया था,जिसकी सूचना उमरियापान थाना प्रभारी सिद्धार्थ राय को मिली। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी सिद्धार्थ राय स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और नहर में डूबे युवक को स्टाफ की मदद से बाहर निकाला। जब युवक को बाहर निकाला गया तो उसकी सांसे चल रही थी,जिस पर उसे तत्काल डायल 100 वाहन से उमरियापान स्वास्थय केन्द्र भेजा गया। जहां उसकी हालत सुधार पर बताई जा रही है। पुलिस ने उसके परिजनों को भी सूचना दे दी है। युवक के परिजनों ने पुलिस की मानवीय पहल के लिए आभार व्यक्त किया है।

शिवपुरी में SC/ST आरक्षण के विरोध में भारत बंद

बसपा और भीम आर्मी ने निकाली रैली, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

कुलदीप गुप्ता । सिटी चीफ
शिवपुरी, शिवपुरी में आज एससी-एसटी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ बसपा, भीम आर्मी समेत अन्य एससी-एसटी संगठनों ने रैली निकाली। साथ ही बाजार को बंद कराया। रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के सष्ट आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया था। शिवपुरी में इस भारत बंद का असर न के बराबर देखने को मिला है। गौरतलब है कि आज शिवपुरी के पुराने बस स्टैंड पर बसपा, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा सहित एससी-एसटी संगठनों के लोग एकत्रित हुए थे। यहां सभी एक रैली के रूप में बाजार से होकर निकले थे। इस दौरान रैली बाजार से शुरू होकर कोर्ट रोड़ होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विगत 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेशित किया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारें सर्वे करायें तथा इन जातियों में क्रीमी लेयर को छांटे और वर्गीकरण भी करें। इसी आदेश के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया एससी-एसटी संगठनों का कहना है कि इस आदेश से अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को काफी नुकसान होगा जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा द्वेष भावना पैदा होगी, फिर भी आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से इन जातियों को नहीं मिलेगा। भारत बंद के दौरान कोई उपद्रव या घटना न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद देखी गई। शिवपुरी एसपी के द्वारा अपील भी जारी की गई थी। आज शहर के बाजारों में पुलिस नजर आ रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। दलित वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। आज रैली के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रैली के साथ चला था।

दिनारा पुलिस की बड़ी कार्यवाही

लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को एक बाइक 2 मोबाइल और लूट में इस्तेमाल कट्टा सहित किया गिरफ्तार

कुलदीप गुप्ता । सिटी चीफ
शिवपुरी, शिवपुरी जिले के दिनारा थाना पुलिस ने 17 अगस्त को दो लोगों के साथ कट्टे की नोक पर लूट करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए दो मोबाइल, दो बाइक , 1100 रुपये नगद और लूट में इस्तेमाल हुआ कट्टा मय राउंड के साथ बरामद किया है। करैरा एसडीओपी शिवनारायण मुकाती ने बताया कि बम्हारी का रहने वाला संजीव जाटव अपने एक साथी के साथ सड़ गांव से अपने गांव बम्हारी लौट रहा था। तभी दिनारा पिछोर रोड पर डामरौनकला मरघट के सामने बाइक सवार बदमाशों ने दोनों के साथ कट्टे की नोक पर मारपीट कर उनके 2 मोबाइल बाइक और रुपये छीनकर भाग गए जिसकी शिकायत दिनारा थाना में दर्ज कराई गई थी। आज पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया है।

शिवपुरी फोरलेन पर ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा

दो यात्रियों की मौत, पुलिस ने ट्रक किया जप्त

कुलदीप गुप्ता । सिटी चीफ
शिवपुरी, शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत सेसई गांव के फोरलेन पर कार से उतरे तीन लोगों को कार सहित ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल हुए एक युवक ने शिवपुरी के जिला अस्पताल और दूसरे की ग्वालियर में मौत हो गई।
घटना आज सुबह के वक़्त की है जब ग्वालियर और भिंड जिले के रहने वाले कार सवार उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन कर ग्वलियर की ओर लौट रहे थे। तभी कार के पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी जिससे भिंड के सिंधहपुरा के रहने वाले सरमन सियोते बाल्मीकी और ग्वालियर के बीरपुरा के रहने वाले चंद्रभान सिंह बघेल और राजा बाल्मीक को ट्रक ने अपनी चपेट में लिया था। जबकि कार के पीछे की साइड खड़े नितिन रजक बाल-बाल बच गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां सरमन सियोते की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं,चन्द्रभान सिह बघेल को ग्वालियर रैफर किया गया था। जहां दोपहर में उन्होंने ग्वालियर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। देहात थाना पुलिस ने ट्रक को जप्त कर जांच शुरू कर दी.

शिवपुरी के हाथरस में बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ अज्ञात लोग कट्टे से फायर कर बुलेरो से फरार हुए

करैरा पुलिस द्वारा एक 315 बोर के देशी कट्टा मय तीन जिन्दा राउण्ड एवं दो खाली चले हुये खोखे और एक बुलेरो गाड़ी सहित पाँच आरोपी गिरफ्तार

कुलदीप गुप्ता । सिटी चीफ
शिवपुरी, शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड के द्वारा जिले में लगातार हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश पर करैरा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हाथरस में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ अज्ञात लोग कट्टे से फायर करके बुलेरो गाड़ी से करैरा तरफ भाग गए हैं सूचना पर पुलिस को उक्त बुलेरो गाड़ी ग्राम जुझाई तरफ आती दिखी जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी भागने लगे जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पाँचो लोगो को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो गाड़ी चालक मनोज लोधी ने बताया कि संकेत जाटव ने ग्राम हाथरस से कट्टे से फायर किया था और कट्टा व तीन जिन्दा राउण्ड व दो चले हुये खाली खोखे बुलेरो की गाडी की आगे की डिग्गी मे रखा होना बताया पुलिस ने एक 315 बोर का देशी कट्टा व 315 बोर के तीन जिन्दा राउण्ड व दो खाली चले हुये खोखे एवं एक बुलेरो कार को जप्त कर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से कट्टे के सप्लायरों के संबंध मे पूछताछ की जा रही है।

बामौरकलां की रहने वाली नन्नू बाई 103 साल में स्वस्थ

विनोबा भावे के आंदोलन में लिया था भाग

कुलदीप गुप्ता । सिटी चीफ
शिवपुरी, अध्यात्म में बड़ी ताकत होती है,इसका जीताजागता उदाहरण हमें शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा के बामौरकलां पंचायत में देखने को मिला। जहाँ बामौरकलां कस्बे में रहने वाली नन्नू बाई का बीते रोज 103वां जन्मदिन मनाया गया। पिछले 40 साल से अधिक समय से अध्यात्म के पथ पर चल रही नन्नू बाई ने आजादी की लड़ाई को करीब से देखा है और विनोबा भावे के आंदोलन से प्रेरित होकर गरीबों को जमींदार से जमीन दान कराई। नन्नू बाई जैन यूपी के ललितपुर जिले के बरौदा स्वामी गांव की रहने वाली हैं शादी के बाद बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु हो गई थी। नन्नू बाई ने बेटे को मात्र 5 साल की उम्र में टीकमगढ़ जिले के पपौरा के गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया था। उस समय नन्नू बाई के घर मे कमाने वाला कोई नहीं था तो नन्नू बाई खुद सामान अपने सर पर रखकर घर घर जाकर सामान बेचा करती थीं इस संघर्ष को पार करते हुए आज नन्नू बाई का 38 लोगों का भरा पूरा परिवार है। नन्नू बाई पिछले 40 साल से अधिक समय से आध्यात्मिक पथ पर है। नन्नूबाई सुबह साढे 3 बजे अपना विस्तर छोड देती है इसके बाद सुबह 6 बजे मंदिर जाती है और 9 बजे वापस आती है,और प्रतिदिन णमोकारी महामंत्र की 108 माला का जाप करती हैं नन्नूबाई अपने बच्चों से कहती है कि निन्ने पानी जे पिये,हरड़ भूंज कर खाऐ, दूध बयारू जो करे ताके घर वैध ना आए। मोटा खाओ मोटा पीयो के सिद्धांत का पालन करने वाली नन्नू बाई का लंबे जीवन का यही राज है। वह घर में लगी हाथ की चक्की से पिसे आटे की रोटी, कुंए का पानी और सूती वस्त्रों का उपयोग करती है। नन्नू बाई के 103 साल की उम्र में न तो दांत टूटे है और न ही आंखों पर चश्मा लगा है।

नन्नू बाई ने बताया कि मेरी दादी ने बचपन से ही मुझे देशभक्ति और समाज सेवा के संस्कार दिए थे। मैं हमेशा उनसे प्रेरित रहती थी, और यही प्रेरणा मुझे भूदान आंदोलन की ओर खींच लाई। एक दिन, गाँव में चर्चा थी कि विनोबा भावे जी पूरे देश में जमींदारों से जमीन मांग रहे हैं, ताकि वह भूमिहीन किसानों में बांट सकें। यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने सोचा कि अगर मैं भी इस आंदोलन में योगदान कर सकूं, तो यह मेरी देश और समाज के प्रति सच्ची सेवा होगी। लोगों ने मुझे समझाया कि मैं अकेली हूं, मेरा बेटा छोटा है, और इस तरह के बड़े कामों में उलझना मेरे लिए सही नहीं होगा। पर मैं अपने इरादों में अडिग थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनूंगी। मैंने गांव की औरतों से बात की। हम छोटी-छोटी सभाएं करने लगे, जहाँ हम विनोबा भावे जी के विचारों को साझा करते और लोगों को इस महान कार्य के लिए प्रेरित करते। मैंने गाँव के ज़मींदार से भी भूदान की अपील की। मेरी मासूमियत और दृढ़ संकल्प को देखकर, उन्होंने आखिरकार कुछ भूमि दान कर दी। वह भूमि बाद में भूमिहीन किसानों में बांट दी गई।उस दिन के बाद से, गाँव में एक नया जोश भर गया। लोग मुझे सम्मान की नजर से देखने लगे। मैं आज भी गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपने गाँव के लोगों के लिए कुछ किया। भले ही मेरे नाम का कहीं जिक्र न हो, लेकिन गाँव के लोग आज भी मेरी कहानी सुनाते हैं। वहीं नन्नू बाई ने बताया कि मैंने 103 साल की उम्र में दो महामारियों हैजा और कोरोना का सामना किया है मैंने किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है। कहा जाता है कि मां के पैरों तले स्वर्ग होता है,संसार में सबसे पहली गुरू मॉ होती है और संसार में सबसे महान है तो वह मां है। नन्नू बाई ने जो गरीबो की हर समय मदद की,स्वयं अपने पैरो पर खडी होकर व्यापार किया। इस कारण ही नन्नूबाई का जीवन दूसरों के लिए दिशा बना,इसका आगे चलकर बेटे को मॉ की विरासत में मिला। नन्नूबाई के बेटे प्रकाश चंद जैन दो बार गांव के ग्राम प्रधान बने,नन्नूबाई के परिवार में अब सदस्यों की संख्या 38 है। कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है,नारी का आगे बढने की प्रेरणा देने वाली नन्नूबाई के परिवार की कई महिला डॉक्टर है और इंजीनियर है। वर्तमान समय में बामौरकला में रहने वाली नन्नू बाई अपने पोते डॉ सी के जैन के साथ निवास कर रही है। डॉ सी के जैन 30 साल पहले बामौरकलां निवास करने आ गए थे।

भीम आर्मी कार्यकर्ता द्वारा क्षत्रिय एवं सवर्ण के खिलाफ दिए गए भाषण पर जताया रोष

राजपूत चेतना मंच कार्यकताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग

गौरव सिंघल। सिटी चीफ।
सहारनपुर । देवबंद, भीम आर्मी कार्यकर्ता द्वारा क्षत्रिय एवं सवर्ण समाज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक बयानबाजी से राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। राजपूत चेतना मंच के कार्यकताओं ने एसडीएम देवबंद अंकुर वर्मा को ज्ञापन देकर आरोपित भीम आर्मी कार्यकर्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। काफी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम अंकुर वर्मा को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि तीन दिन पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने एक धरना-प्रदर्शन के दौरान राजपूत व सवर्ण समाज के खिलाफ जमकर जहर उगला था। जिसकी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी जमकर प्रसारित हो रही है। इस अनर्गल बयानबाजी से क्षत्रिय समाज आहत है। संगठन संचालकों की सहमति से ऐसे लोग समाज में वैमनस्य फैलाने और जातीय संघर्ष कराने का कुत्सित प्रयास कर रहे हे। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने वाले अधिवक्ता ठा. सुरेंद्रपाल सिंह, कुलदीप राणा, मोहित, सत्य, अक्षय, रवि, रूप सिंह, सुधीर और अमरीश समेत आदि मौजूद रहे।

सड़को पर चौपाया, कॉउ केचर सक्रीय

शहडोल के अलग अलग स्थानों से आवारा मवेशियों को गौशाला भिजवाया गया

मोहम्मद मुनीर | सिटी चीफ | शहडोल, लेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी शहडोल अक्षत बुंदेला के निर्देशन में शहडोल नगरपालिका अंतर्गत सड़कों में घूम रहे आवारा मवेशियों को प्राथमिकता के साथ गौशालाओं में भिजवाया जा रहा है। इसी कड़ी में कॉउ केचर द्वारा शहडोल नगर के लल्लू सिंह चौराहा सहित अन्य स्थानों से आवारा मवेशियों को गौशाला भिजवाया गया है।

बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल सरकार तत्काल घोषित करें -भगत सिंह वर्मा

अन्नदाता किसानों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी :- भगत सिंह वर्मा

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने ग्राम झबीरण में किसानों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की योगी सरकार और मोदी सरकार देश के अन्नदाता किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अन्नदाता किसानों ने मेहनत करके खाद्यान्न के भंडार भरकर देश को आत्मनिर्भर बनाया है। इसके बावजूद भी देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है जिसके कारण देश के अन्नदाता किसान कृषि प्रधान देश में कर्ज बंद होकर आत्महत्या कर रहे हैं। जिसके लिए दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि गन्ना सभी प्रदेशों व देश की आर्थिक रीढ़ है। गन्ने से अल्कोहल और अल्कोहल से हजारों उत्पाद तैयार होते हैं जिसे प्रदेश और केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये एक्साइज ड्यूटी व जीएसटी के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद भी गन्ना किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल सरकार नहीं दिला पा रही है। भगत सिंह वर्मा ने बताया कि एक कुंतल गन्ने से 12 किलोग्राम से अधिक चीनी बन रही है, 5 किलोग्राम शीरा बन रहा है, 30 किलोग्राम खोई बन रही है, 4:30 किलोग्राम मैली प्रेसमड बन रही है। अकेले 5 किलोग्राम सिरे से एक बल्क लीटर अल्कोहल बनता है। जब यह देसी शराब में प्रयोग होता है तो सीधा सरकार के खाते में 700 एक्साइज ड्यूटी के रूप में जमा हो जाता है और अंग्रेजी शराब पर तो 1000 रूपए से ऊपर सरकार के खाते में जाता है। और 500 से अधिक चीनी बनती है और 100 की खोई बन जाती है। इस सबके बावजूद भी गन्ना किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य तो दूर लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है। एक कुंतल गन्ने की उत्पादन लागत 550 रुपए कुंतल है। डॉ एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 प्लस 50% के अनुसार गन्ने का लाभकारी मूल्य 825 रुपए कुंतल होना चाहिए। भगत सिंह वर्मा ने भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल तत्काल घोषित करने, चीनी मिलों से बकाया गन्ना भुगतान व ब्याज तुरंत दिलाने चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से धुलाई किराया न काटने, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए कमाने वाली चीनी मिल को गन्ना एक्ट के अनुसार क्षेत्र के विकास में धन खर्च करने चीनी मिल को अपने क्षेत्र में स्कूल स्थापित करके गन्ना किसानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने, किसानों को निःशुल्क चिकित्सा दिलाने, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराने की मांग की गई। बैठक का संचालन करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है इसलिए इसको चार भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए जिससे गन्ना किसानों की समस्याएं तुरंत हल हो सके। डॉ अशोक मलिक ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है इस बार गन्ना किसान चुप बैठने वाले नहीं है। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक ने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा से वार्ता करके प्रदेश और देश के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल दिलाना चाहिए। असीम मलिक ने कहा कि वर्ष 1967 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह होते थे उसे समय गन्ने का मूल्य 12 रूपए 10 पैसे कुंतल था। उस समय प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी 70 प्रतिमा थी। इस हिसाब से गन्ने का मूल्य 12 हजार100 कुंतल होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता अरविंद मुखिया ने की। बैठक में चौधरी धीर सिंह, बाबू अशोक चौधरी, अरविंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी, मुनेश चौधरी, अनुज कुमार, मोहम्मद अकमल वली उल्लाह, हरपाल सिंह, जोगिंद्र सिंह, कालू सिंह, सुधीर चौधरी, पिंटू चौधरी आदि ने भाग लिया।

आफत में जान नगरपालिका बन रही अनजान....?

लोगों के घरों में भरा पानी, लाखो का नुकसान

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ ।
शहडोल, इन बीते दो तीन दिनों में हुए बारिश में नगरीय प्रशासन के दावों की तो पोल ही खोल कर रख दी है, शनिवार को रीवा होटल के पास वार्ड नंबर 23 एलआईसी के सामने 2 घंटे की इतनी तेज बारिश में नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी, घटिया पुलिया के निर्माण कार्य ने न सिर्फ लोगों के घरों में पानी भरा बल्कि उनके घरों के सामान सहित काफी नुकसानी का सामना करना पड़ा पत्रकार साथी गणेश कुमार केवट के घरों में भरा हुआ पानी का वीडियो और तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि उसके घरों में इलेक्ट्रॉनिक का सामान फ्रिज वाशिंग मशीन सहित कपड़े कॉपी किताब दवाईयां सहित घरेलू सामान का काफी नुकसान हुआ और उनकी मां जो अपाहिज और बीमार है वह पलंग में बैठे हुए कमरे में भरे हुए पानी का नजारा और उनके मन का दहशत इस बात को बयां कर रहा हैऔर उनकी गाड़ी फोर व्हीलर और टू व्हीलर में भी पानी भर गया साथ-साथ बगल में रहने वाले निवासी उमेश कुमार दंड मिश्रा, नागरत, सोनू जायसवाल सहित उनके घर और दुकानों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है और सामान की काफी क्षति पहुंची है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वह नगर पालिका को दे रहे हैं और आगे इस प्रकार की पानी की समस्या ना हो उसके लिए उन्होंने आज दिनांक 20.8.2024 को संभागायुक्त कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल को ज्ञापन देते हुए अपनी पूरी व्यथा को बताया और उनका वीडियो फोटो भी दिखाया उन सभी वार्ड वासियों और रहवासियों का कहना है कि जो पुलिया का निर्माण हुआ है वह सही तरीके से नहीं हुआ है बुढार चौक से लेकर बड़ेरिया भवन के. स्क्वायर .तक सभी का पानी का निकासी का एक मात्र पुलिया है जिसको चौड़ी ना बनाकर गुणवत्ताहीन काम किया गया जिससे हम आम जनों के घरों में पानी भरा है इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका और प्रशासन की होती है इस दिशा में उन्होंने जनवरी और मार्च के महीने में भी ज्ञापन को देखकर इस बात को जताया था की बरसात के पहले सही तरीके से पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो हमारे घरों में पानी भरेगा जिस पर नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया यह जांच का विषय बनता है और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उसे समय यह सही पुलिया का निर्माण होता तो आज यह स्थिति देखने को नहीं पड़ती उनका यह भी कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है और किसी की जान भी जा सकती थी उसकी भरपाई नगर पालिका वा प्रशासन द्वारा की जाए और भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो इसकी जिम्मेदार नगर पालिका और प्रशासन की होगी आज ज्ञापन देते हुए सभी वार्ड वासी मिश्रा जी उमेश कुमार दंड गणेश केवट सोनू जायसवाल नागरत जी अंकित श्रीवास्तव शुभम गुप्ता आदित्य गुप्ता राधे गुप्ता संदीप गिरी शेखर दंड एवं वार्ड वासी उपस्थित रहे।

प्रतिक्रिया...

एसडीएम शहडोल मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत निर्देश देके समस्या का समाधान करता हूं।
घनश्याम जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् शहडोल
तुरंत फोन करके इंजीनियर को भेजता हूं और मैं स्वयं आता हूं स्पॉट पर समस्या का निदान करते हैं, डॉली शर्मा जी से फोन में बात हुई उनका कहना है कि 2 दिन त्यौहार के बाद 4 फीट का डोला नाली में डलवा के नाली सही करेंगे और पुलिया के लिए इंजीनियर से बात करके निराकरण निकलेंगे।
प्रवीण शर्मा, डोली उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद् शहडोल

भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की मंशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 अगस्त को मीरापुर में टटोलेंगे कार्यकर्ताओं का मन

सुरेंद्र सिंघल/गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

मीरापुर । मुजफ्फरनगर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 10 सीटों के उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहल करते हुए उपचुनावों में जीत दर्ज कर अपनी ताकत और प्रासंगिकता दोनों प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसी मंशा के साथ योगी आदित्यनाथ गुरूवार 22 अगस्त को मीरापुर मंडल विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। वह मीरापुर स्थित बीआईटी कालेज में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के मन की टोह लेंगे। बिजनौर के रालोद सांसद चंदन चौहान ने आज वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंघल को बताया कि उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान मीरापुर में बड़ी रैली में आने की दावत दी थी लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मीरापुर आ रहे हैं। ध्यान रहे 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा समर्थित रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान मीरापुर से विधायक चुने गए थे। जो हालिया लोकसभा चुनाव में बिजनौर से रालोद के टिकट पर भाजपा के समर्थन से सांसद चुने गए और उन्होंने मीरापुर सीट से इस्तीफा दे दिया था जिससे मीरापुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होना है लेकिन अभी चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ-साथ रालोद-भाजपा गठबंधन और सपा-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। भाजपा-रालोद गठबंधन में संभवत: इस सीट पर रालोद चुनाव लड़ेगी और सपा-कांग्रेस गठबंधन में अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह सीट किसके खाते में जाएगी। इस सीट पर सवा लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं जो निर्णायक रहने वाले हैं इसके अलावा जाट, गुर्जर और सैनी मतदाताओं की बहुलता है। दलित वोटों की संख्या भी काफी है।

सहस्त्रडोल की नगरी और दम तोड़ते तालाब, अधिकारियो की चुप्पी

विश्व हिन्दू महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कलेक्टर , कमिश्नर सहित सीएम को लिखा पत्र

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ ।
शहडोल, भले ही भाजपा सरकार जल स्त्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चला रही है, लेकिन शहडोल में इस अभियान कि हवा कथित कांग्रेसी नेता निकलने का काम कर रहे है, इस मामले में ताजुब कि बात यह भी है कि विपक्षी दलों के तथाकथित नेताओ को इस अवैध कारोबार को बल वर्षो से एक ही स्थान पर पदस्थ राजस्व एवं पुलिस का अमला प्रदान करता है, इस तरह कि ढेरो शिकायतों कि फाइल सम्बंधित कार्यालयों में धूल फांक रही है, मामले में हालिया शिकायत विश्व हिन्दू महा संघ भारत की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह ने की है। शिकायतकर्ता की लिखित शिकायती पत्र के अनुसार भूमाफिया अभिषेक मिश्रा पिता नारायण मिश्रा निवासी पुरानी बस्ती ने कई नजूल एवं शासकीय सहित आदिवासियो की भूमि में कब्जा कर रखा है, इसका प्रमाण नगरपालिका अंतर्गत खसरा नंबर 516 की शासकीय भूमि मेरी शिकायत सही पाए जाने पर तहसीलदार एवं अनुभाग कार्यालय के जारी आदेश में भूमाफिया से अतिक्रमण मुक्त कराई गयी। इसी तरह भूमाफिया ने शहर का हृदय स्थल में कब्जा जमाया हुआ है। महिला समाजसेवी एवं शिकायतकर्ता ने शहडोल के राजस्व अभिलेखों को आजादी के बाद से खंगाले है उन रिकॉर्ड के मुताबिक खसरा नंबर 97 में दर्ज तालाब भीठा की भूमि पर यह समझ से परे है है की वर्ष 2014 आते आते जिम्मेदार अफसरों की आँखों में धूल झोंककर बाक़ायदा विवादित उक्त भूमि का बटवारा और नामंतरण दर्ज करते हुआ पट्टा हथिया लिया है, जबकि मामले में खसरा नंबर 97 का इतिहास आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन से पता चलता है, जो भूमि 1950 -51 से लेकर 1990 91 92 93 94 के राजस्व अभिलेखों में शासकीय तालाब भीठा दर्ज आखिर कैसे शहर के मध्य का एक एकड़ से अधिक की भूमि पर कब्ज़ा हो गया। राजस्व मामले में चला पेशियों के आधार पर पता चलता है की इस तालाब पर कब्जा करने की नियत से पहले सिंघाड़ा की खेती का नाम लिया गया, कभी गाय पाली गई डेयरी दिखाई, तो कभी लकड़ी का टॉल बनकर रखा गया, यह सब कही सुदूर गर्मी बस्ती में नहीं शहर के बीचो बीच हुआ ऐसा स्कैम है जैसे आँखों से काजल चुरा लेना कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

शहडोल की वर्तमान स्थित
एमपी का एकलौता जिला शहडोल जहा शहर में 365 तालाबों का इतिहास ऐतिहासिक पौराणिक कथाओ के पन्नो में दर्ज है लेकिन बामुश्किल वर्तमान नगरपालिका में सिर्फ 44 तालाब तालाबों की वजह से जाना जाने वाले शहडोल नगर में अब गिनती के तालाब बचे हैं। शहडोल नगर का 365 तालाबों का इतिहास है। अब नगर पालिका के रिकार्ड में 44 शासकीय तालाब ही दर्ज हैं। जबकि 10 निजी तालाब है। इसके अलावा सोहागपुर तहसील में तालाब 561 दर्ज हैं। इसमें शासकीय अशासकीय सभी शामिल हैं। कई तालाबों में बड़े कॉलोनाइजरों ने गरीबों को आगे करके भूमि पर कब्जा कर लिया है।

तालाबों का कैचमेंट एरिया समाप्त नगर के जिन तालाबों का नगर पालिका द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है उनकी स्थिति और बद से बद्तर हो गई है। कंक्रीट कार्य और कैचमेन्ट एरिया समाप्त होने की वजह से इनमें जल भराव ही नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते अन्य माध्यमों से तालाबों को भरने की कवायद की जा रही है। घरौला तालाब और मोहन राम तालाब की यही स्थिति है। शहर के अधिकांश तालाबों की मेढ़ में कुछ मकान पूर्व से ही बने हुए हैं तो कुछ नए निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। निर्माण कार्य की आड़ में तालाब को भांटने का काम भी किया जा रहा है। जिसके चलते दिन प्रतिदिन यह तालाब सिकुड़ता जा रहा है।

क्या कहता है इतिहास...
गौरतलब है ऐतिहासिक पौराणिक कथाओ के मुताबिक शहडोल का असली नाम सहत्रडोल है जहा अज्ञात वास के दौरान राजा विराट के नगर में एक वर्ष में भीम ने अपनी गदा से हर दिन एक तालाब नुमा गड्ढे बने। 365 तालाब वाले शहर शहडोल में आज 65 तालाब नहीं बचे है, एक सर्वे के मुताबिक वैज्ञानिक आधार पर बने शहडोल में 365 तालाब का आपस में ऐसा कम्युनिकेशन था की एक तालब ऊपर उसके नीचे दूसरा फिर तीसरा चौथा क्रमश: तालाब की श्रृंखला थी आज वो सभी एक दूसरे से जुड़े कैचमेंट एरिया भी अतिक्रमण की चपेट में है, यद्यपि तालाब पर से बेजा कब्ज़ा नहीं हटवाया गया तो शहडोल की जनता को पेयजल आपूर्ति से जूझना पड़ेगा, भविष्य में पीने का पानी को शहर में त्राहिमाम मचेगा।

केवल अफसरों ने यह किया
नगर के तालाबों को संरक्षित करने के लिए बैठकें तो कई बार हुई लेकिन बैठकों में बनी कार्य योजना व अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन होते नजर नहीं आ रहा है। कलेक्टर द्वारा बैठक में तालाबों की साफ-सफाई के साथ ही उनके संरक्षण की बात कही गई थी। इसके बाद स्थितियां जस की तस बनी हुई है। अफसर मैदानी अधिकारियों को निर्देश देते रहे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल मामले में हालही में तात्कालिक कलेक्टर ललित दाहिमा ने तालाबों के अतिक्रमण मामले में बैठक लेकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी लेकिन लेकिन मैदानी अमला तालाब मामले की फाइल ही दबा कर बैठ गए।

कोर्ट का आदेश हटाओ बेजा कब्ज़ा.....
बीते दिनों उत्तरप्रदेश में दायर की जनहित याचिका पर तालाब में किये गए अतिक्रमण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके बाद से ही राज्य सरकारों ने तालाब के संरक्षण एवं उनके जीर्णोद्धार पर जोर देना शुरू किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में सन 1951-52 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों से अतिक्रमण हटा कर और तालाबों की जमीन पर दिए गए पट्टे समाप्त कर उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया । इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को राजस्व परिषद के चेयरमेन के परामर्श से इस संदर्भ में एक मानीटरिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व अफसरों को आदेश दिया जाए कि तालाबों की सूची तैयार करें एवं तालाबों पर हुए अतिक्रमण का खाका तैयार करें । तालाबों से अतिक्रमण हटा कर बहाली रिपोर्ट पेश करें। सरल शब्दो में कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को तालाबों से अतिक्रमण हटा कर उनकी पुर्नबहाली करने का आदेश दिया, एनजीओ द्वारा दायर याचिका का उद्देश्य भी यही था की तालाब का जीर्णोद्धार हो हुए बेजा कब्ज़ा हटाया जाये, कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में यद्यपि लापरवाही बरती जा रहीं है तो उनके खिलाफ भी संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा यदि किसी तालाब पर पट्टे दिए गए हैं तो जिलाधिकारी कानूनी कार्रवाई करें और अवैध कब्जे हटा कर उसे बहाल किया जाए।

दो लाख के लेनदेन को लेकर 11 वर्ष पूर्व हुई अधिवक्ता के पुत्र की हत्या के मामले में हुई सुनवाई

तीन को हुई आजीवन कारावास की सजा

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।
सहारनपुर, एडीजे कोर्ट कक्ष संख्या-3 ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद मित्तल के बड़े पुत्र अंकित मित्तल की 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तों लोकेश गर्ग पुत्र देवेंद्र गर्ग निवासी माधव विहार कालोनी, थाना मंडी सहारनपुर, अजय गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता और नेत्रपाल पुत्र पवन गुर्जर निवासी गदरहेड़ी, थाना सरसावा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील दीपक सैनी ने बताया कि इस मामले में कुल पांच आरोपी थे जिनमें से दो आरोपियों सुनील गर्ग पुत्र धनीराम गर्ग और नरेंद्र पुत्र सुरेंद्र की मुकदमें के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक लाख 60 हजार प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया। वकील के मुताबिक 13 जनवरी 2013 को अधिवक्ता प्रमोद मित्तल का 27 वर्षीय बड़ा पुत्र अंकित मित्तल घर से गायब हुआ था। जिसकी प्रमोद मित्तल ने कोतवाली मंड़ी में गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में अंकित मित्तल का शव सरसावा थाने के गांव गदरहेड़ी के गन्ने के खेत में दबी हालत में बरामद हुआ था। हत्या का कारण अंकित मित्तल के लोकेश गर्ग पर दो लाख रूपए कर्जे का होना था। अंकित अपने रूपयों की मांग कर रहा था।

गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी पहुंच गयी पुलिस

संपत्ति विवाद में पिता की पीट-पीटकर कर दी हत्या

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । शहडोल, कोतवाली थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद पर सौतेले पुत्र ने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी है, लाठी डंडों से सौतेले पुत्र ने पिता को पीट-पीट कर गंभीर घायल कर दिया जिसके बाद पिता की घर में कुछ देर बाद मौत हो गई, मौत के बाद भी आरोपी ने इसकी खबर किसी को नहीं दी और शव का अंतिम संस्कार करने की आरोपी मंगलवार तैयारी कर रहा था तभी पुलिस पहुंच गई।

मौत के मामले का रहस्य बताया गया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरी टोला जुगवारी के रहने वाले दादूराम सिंह उम्र 50 वर्ष की इस घटना में मौत हुई है, हत्या करने वाला आरोपी मृतक का सौतेला पुत्र रंजीत सिंह है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पुलिस के अनुसार रंजीत मृतक दादूराम का सौतेला पुत्र है,और आए दिन संपत्ति की बात को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ करता था, रक्षाबंधन की रात सौतेले पुत्र का मृतक से विवाद हुआ, तभी घर में रखी लाठी से आरोपी ने दादू राम को पीट-पीट कर गंभीर घायल कर दिया,कुछ देर बाद दादू राम की घर पर मौत हो गई, मौत के बाद आरोपी ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी, आरोपी की मां और बहने भी घर में मौजूद थी लेकिन उन्होंने भी गांव के किसी भी व्यक्ति को इसकी कोई खबर नहीं दी।

पूछताछ में खुल गया मामला... जब सुबह पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दादू राम के घर पहुंच उसे आवाज दी लेकिन दादू राम घर से नही निकला तभी आरोपी सौतेला पुत्र सामने आया जिससे पूछताछ की लेकिन आरोपी घबरा गया और सही जवाब पड़ोसी को नहीं दे सका, संदेह होने पर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने मंगलवार की सुबह

ही पुलिस को मामले की खबर दी, जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तब आरोपी अपने सौतेले पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है।

प्रतिक्रिया.... संपत्ति विवाद में सौतेले पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है, लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या करने की बात सामने आई है। पीएम रिपोर्ट के बाद और भी स्पष्ट हो सकेगा, अभी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताझ की जा रही है।
रावेंद्र तिवारी, थाना प्रभारी थाना कोतवाली, शहडोल

मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय को किया संबोधित

कहा- युद्ध नहीं, शांति में भरोसा रखता है भारत

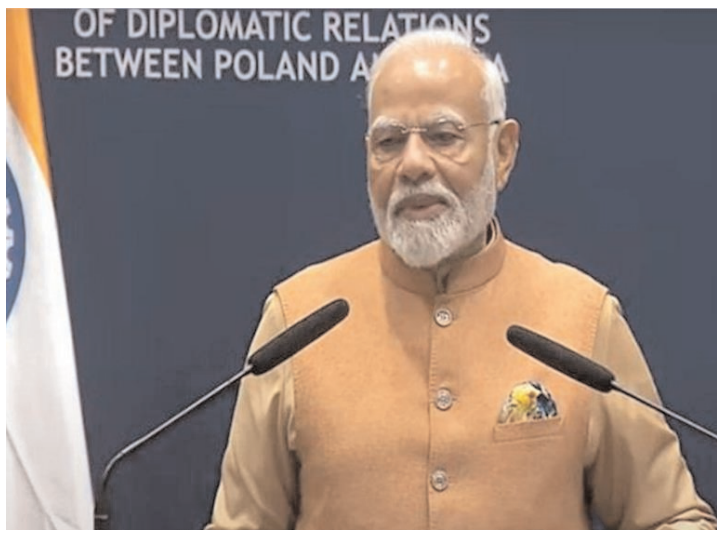

इंटरनेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पोलैंड यात्रा से भारत और पोलैंड के द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आएगी। मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा अपने सम्मान में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। मोदी दो दिन की यात्रा पर बुधवार को वार्सा पहुंचे। उनकी आज राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत होगी।

मोदी ने भारतीय समुदाय को भारत की विकास यात्रा का भागीदार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और पोलैंड के बीच सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस यात्रा में कल पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ गुरुवार को होने वाले उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। मोदी ऐसे समय पोलैंड आएं है जबकि दोनों देश अपने राजनयिक संबंध की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री 45 वर्ष बाद पोलैंड की यात्रा पर आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत तथा पोलैंड के साझा मूल्य दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को निकालने में पोलैंड की ओर से मिली मदद के लिए पोलैंड सरकार का आभार जताया। मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को भारत के पर्यटन का ब्रांड अम्बेस्डर बनने और हर साभ पोलैंड के पांच पांच परिवारों को भारत भ्रमण के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

मोदी ने इस अवसर पर पोलैंड के साथ जामसाहब स्मारक युवा विनियम कार्यक्रम शुरू किए जाने की भी घोषणा की पोलैंड के 20 युवाओं को हर वर्ष भारत आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात भूकंपन के समय सबसे पहले सहायता लेकर पुंचे देशों में पोलैंड आगे था। मोदी ने कहा कि डोबरी महाराजा कोल्हापुर और मौंटे कैसिनों युद्ध स्मारक भारत और पोलैंड की जनता के बीच संबंधों का उदाहरण हैं।

मोदी ने कहा , ' पहले भारत सारे देशों से समान समान दूरी बनाए रखो की नीति पर चलता था, आज हमारी नीति है कि सारे देशों से समान नजदीकी बना कर चलने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, आज का भारत सबके विकास की बात करता है आज का भारत सबके साथ है सबके हित के बारे में सोचता है। मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है और पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी यही अनुभव हो रहा होगा।

तियानमेन कार्यकर्ता पर तांग पर अमेरिका में चीन के लिए जासूसी का आरोप

न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों ने तियानमेन स्क्वायर के पूर्व लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता युआनजुन तांग पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। तांग, जो कभी चीन में लोकतंत्र की मांग के लिए तियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शन करने वालों में से थे, अब चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (स्स्स्) के लिए गुप्त रूप से काम करने के आरोप में घिरे हैं।

अभियोजन के अनुसार, तांग ने 2018 में एक चीनी खुफिया अधिकारी के साथ सहयोग करना शुरू किया। यह दावा किया गया है कि तांग ने अमेरिका में स्थित लोकतंत्र समर्थक समूहों पर नजर रखी और उनकी गतिविधियों की जानकारी उस खुफिया अधिकारी को भेजी। तांग पर आरोप है कि उन्होंने न केवल अमेरिका में हो रहे लोकतंत्र समर्थक कार्यक्रमों की जानकारी साझा की, बल्कि एक चीनी असंतुष्ट की कांग्रेस की चुनावी मुहिम से जुड़ी गोपनीय जानकारी भी उस अधिकारी को दी।

तांग के इस कथित सहयोग के पीछे का कारण भी खुलासा हुआ है। अदालत के दस्तावेजों में बताया गया है कि तांग को चीन में अपने परिवार

से पुनः मिलाने का वादा किया गया था, जिसके बदले में उन्होंने यह जासूसी की।अब तांग पर अमेरिकी न्याय प्रणाली के तहत जासूसी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

यह मामला दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे चीन अपनी घरेलू असंतुष्टों पर नज़र रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तांग का यह मामला न केवल अमेरिका में रहने वाले चीनी असंतुष्टों के लिए, बल्कि विश्वभर में लोकतंत्र समर्थकों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

पहाड़ी इलाके में पलटी बस; 35 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की गई जान

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान के यज़्द प्रांत में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें इराक जा रहे पाकिस्तानी शिया तीर्थयात्रियों की बस पलट गई। इस हादसे में 35 लोगों की जान चली गई, जबकि 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के समय बस में कुल 51 यात्री सवार थे। यह दुर्घटना मंगलवार रात को हुई, जब तीर्थयात्री अरबईन के मौके पर इराक के कर्बला जा रहे थे।

अरबईन, शिया मुस्लिम समुदाय के लिए एक विशेष धार्मिक अवसर है, जो 7वीं शताब्दी में इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन मनाया जाता है। हर साल, लाखों तीर्थयात्री कर्बला जाते हैं, जहां इमाम हुसैन की मजार स्थित है। स्थानीय आपातकालीन अधिकारी मोहम्मद अली मालेकज़ादेह के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस तेज़ गति से नियंत्रण खो बैठी और पलट गई।

यह हादसा यज़्द प्रांत के एक पहाड़ी इलाके में हुआ, जहाँ सड़कें

संकरी और खतरनाक हैं। घटनास्थल पर स्थानीय बचाव दल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंचीं। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाज़ुक बनी हुई है। कई घायलों को विशेष इलाज के लिए अन्य शहरों के बड़े अस्पतालों में भेजा गया है। इस हादसे ने दोनों देशों में शोक की लहर पैदा कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। वहीं, ईरान में भी इस दुर्घटना को लेकर विशेष जांच शुरू कर दी गई है ताकि दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाया जा सके।

यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब अरबईन के मौके पर तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी इज़ाफ़ा होता है, जिससे सड़क पर यातायात का दबाव भी बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

बिहार में गाड़ियों का पंजीकरण हुआ सस्ता अब सिर्फ 4000 में होगा कार का रजिस्ट्रेशन

पटना। बिहार सरकार ने वाहनों का राज्य में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल से लेकर कैब के रूप में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क को करीब 80 प्रतिशत तक घटा दिया।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि वाहनों के पंजीकरण शुल्क घटाने के लिए मोटर वाहन नियमावली 1992 के नियम 74 और 82 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नियम में मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क का निर्धारण होता है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस प्रावधान के तहत दोपहिया वाहनों पर लगने वाला पंजीकरण शुल्क 1500 रुपए से घटकर 1050 रुपए, आटोरिक्शा पर 5650 कम होकर 1150 रुपए और कैब के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 23650 रुपए से घटकर 4150 रुपए हो गया है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि पंजीकरण शुल्क में कमी किए जाने का करना बिहार में वहनों की बिक्री में बढ़ोतरी करना और रजिस्ट्रेशन की संख्या में इजाफा करना है ताकि यह शुल्क बिहार को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि पहले पड़ोस के राज्यों के रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार से कम था जिसकी वजह से लोग अन्य राज्यों से वाहन खरीद लेते थे।

संपन्न हुई अमरनाथ यात्रा, इतने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

जानें कितने सालों का टूटा रिकॉर्ड

जम्मू-कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस साल रिकॉर्ड संख्या में 5.12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए तीर्थयात्रा 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को संपन्न हो गई। शाह ने सोशल

मीडिया मंच 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 52 दिनों तक चली यात्रा में इस बार रिकॉर्ड 5.12 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए, जो कि बीते 12 वर्षों की सर्वाधिक संख्या है। गृह मंत्री ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उनके सभी सुरक्षाकर्मियों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने में सभी का अद्वितीय योगदान रहा है।

शौच के लिए गई नाबालिग को 3 युवकों ने उठाया

फिर चलती कार में किया सामूहिक दुष्कर्म....बाद में सड़क पर फेंककर हुए फरार

झांसी। उत्तर प्रदेश में झांसी के प्रेमनगर थानाक्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। जहां पीड़िता के परिजनों ने बताया कि युवती मंगलवार सुबह शौच के लिए गई थी और इसी दौरान तीन युवकों ने उसको जबरदस्ती खींचकर कार में डाल लिया तथा कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। अपराध को अंजाम देने के बाद तीनों युवक पीड़िता को रक्सा थानाक्षेत्र में करौंदी माता मंदिर के पास छोड़ कर चले गए और जाते समय पीड़िता को धमकी देकर गए कि अगर उसने किसी से भी इस बारे में बताया तो उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही करेंगे।

परिजनों के अनुसार पीड़िता की उम्र 17 साल है और वह अपनी बुआ के घर आई हुई थी जहां उसके साथ तीन युवकों ने सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया। युवती

ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरा मामला बताया। इसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत थाने में दी। परिजनों ने बताया कि तीनों आरोपी गांव के ही हैं और उनमें से दो सोनू और मनीष उनके परिचित हैं साथ ही इनका घर में आना जाना था। इनके अलावा अपराध को अंजाम देने वाला तीसरा आरोपी अंजान है। क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी ने आज बताया कि प्रेमनगर थानाक्षेत्र के बिजौली चौकी क्षेत्र निवासी पीड़िता ने लिखित शिकायती पत्र देकर सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन का काम किया जा रहा है ,प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ 9 और मुकद्दमे दर्ज, कुल 33 मामले फाइल

ढाका। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 86 अन्य के खिलाफ सिलहट शहर में एक जुलूस पर हमला करने के मामले में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस महीने की चार तारीख को बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। हसीना ने देश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया था और तब से अबतक उनके खिलाफ कुल 33 मामले दर्ज किए गए हैं। जातीयतावादी छात्र दल की सिलहट शहर इकाई के कार्यवाहक अध्यक्ष जुबेर अहमद ने सिलहट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमन भुइया की अदालत में मामला दर्ज कराया। हसीना की बहन शेख रेहाना को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

द डेली स्टार अखबार ने मामले के विवरण के हवाले ये खबर दी कि आरोपियों ने चार अगस्त को सिलहट शहर के बंदरबाजार क्षेत्र में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा आयोजित एक शांतिपूर्ण रैली पर हमला किया, जिसमें कई लोगों को गोली लगी और वे घायल हो गए। खबर के मुताबिक, अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन मंत्री अब्दुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान, पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व कानून मंत्री अनीसुर रहमान और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार सलमान एफ रहमान सहित अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। अखबार के मुताबिक, इस मामले के साथ ही हसीना पर अब 33 मुकदमे दर्ज हो गए हैं,

जिनमें 27 हत्या के, चार मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के तथा एक अपहरण का मामला शामिल है। हसीना सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा देकर पांच अगस्त को भारत भाग गईं।

बांग्लादेश में हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर अंतरिम सरकार बनाई गई है और 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को इसका मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हाल ही में हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाएगी। हसीना सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में बांग्लादेश में 230 से अधिक लोग मारे गए, जिससे सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य में छात्रों द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद से मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो गई।

शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गईं, जिससे उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 33 हो गई, जिनमें हत्या के 26, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के चार और अपहरण के एक मामले शामिल हैं।डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के वकील गाजी एमएच तमीम ने हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव (शिक्षा और कानून) मुफ्ती हारुन इजहार चौधरी की ओर से बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569